

त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है।

03 अंकशास्त्र में पिनकल्स (Pinnacles) और चैलेंजेस (Challenges)

06 युवा बजट 2026-27 के आर्थिक मान्ये विशिष्ट, विकसित भारत 2047 के सपने होंगे

08 वित्त मंत्री निर्मला का हुआ निर्देश, मानसिक स्वास्थ्य व तकनीका विज्ञान का दुसरा अस्पताल पुनः रांची में

“बजट 2026-27: आम जनता के लिए समृद्धि का नया द्वार”

संजय कुमार बाटला

भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2026-27 आम जनता के लिए समावेशी विकास, रोजगार सृजन और जीवन स्तर सुधार पर केंद्रित है। यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से भरा पड़ा है, जिससे दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।



संजय कुमार बाटला

सृजित होंगे। *हर जिले में गलस हॉस्टल बनाना महिलाओं की शिक्षा व रोजगार को बढ़ावा देगा। *खेलो इंडिया मिशन का विस्तार खेलप्रतियोगियों के लिए अवसर खोलेंगे।

करदाताओं व मध्यम वर्ग को राहत *वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय छूट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख। *TDS छूट सीमा बढ़ी।

*विदेशी टूर पैकेज पर TCS दरों में कटौती से यात्रा सस्ती हुई। *विवाद से विश्वास योजना का विस्तार कर विवादों को आसानी से सुलझाने की सुविधा। *छोटे करदाताओं के लिए सरलीकृत प्रक्रिया से समय व धन की बचत

स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचे में सुधार *कैसर दवाओं के दाम घटाने, *मेंडिकल टूरिज्म हब बनाने से इलाज सुलभ व सस्ता होगा।

*1.5 लाख करोड़ का ब्याज - मुक्त ऋणों को ईफ़ेक्टिव कर के लिए, जिससे सड़क, रेल व बिजली सुविधाएं बेहतर होंगी। *पर्यटन व सांस्कृतिक विकास से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा।

प्रमुख लाभों का सारांश
1. किसान/ग्रामीण- डिजिटल कृषि, KCC वृद्धि, पशुपालन रोजगार
2. युवा/रोजगार- ई-बस, हाई-स्पीड रेल, MSME क्रेडिट
3. मध्यम वर्ग- टैक्स छूट, TCS कटौती, रिटर्न सुधार
4. महिलाएं/वृद्ध- गलस हॉस्टल, ब्याज छूट वृद्धि
5. स्वास्थ्य- कैसर दवा सस्ती, मेंडिकल हब

यह बजट समृद्धि के साथ स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिससे आम जनता का क्रय शक्ति बढ़ेगा और भविष्य सुरक्षित होगा।

भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2026-27 आज पेश किया गया, जिसमें व्याज, घाटे और राज्यों को हस्तांतरण का स्पष्ट सार प्रस्तुत किया गया।

प्राथमिक घाटा (पीडी) प्रमुखता से दर्शाए गए हैं। राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को दिए जाने वाले संसाधनों व योजनाओं का सारांश भी शामिल है।

घाटों के अर्थ
राजकोषीय घाटा (एफडी) कुल व्यय और कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियां छोड़कर) के बीच का अंतर है, जो सरकार की उधारी जरूरत बताता है। राजस्व घाटा (आरडी) तब होता है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो; प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी) में पूंजीगत संपत्तियों हेतु सहायता अनुदान घटाया जाता है; प्राथमिक घाटा (पीडी) एफडी से ब्याज भुगतान घटाकर निकाला जाता है। प्रभावी पूंजीगत व्यय (एफ-कैपेक्स) पूंजीगत व्यय और सहायता अनुदान का योग है।

व्यय के अनुमान
संशोधित अनुमान (आरई) 2025-26 में कुल व्यय ₹49,64,842 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹10,95,755 करोड़ का अनुमान है, जो पिछले वार्षिक ₹46,52,867 करोड़ से अधिक है। बजट अनुमान (बीई) 2026-27 में कुल व्यय ₹53,47,315 करोड़, पूंजीगत व्यय ₹12,21,821 करोड़ और प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹17,14,523 करोड़ रखा गया।

पूंजीगत व्यय ₹12,21,821 करोड़ और प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹17,14,523 करोड़ रखा गया।

राज्यों को हस्तांतरण
2026-27 के बजट में राज्यों को कुल ₹25,43,769 करोड़ के संसाधन हस्तांतरित करने का अनुमान है, जिसमें राज्य का कर हिस्सा, अनुदान/ऋण और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। यह 2024-25 के वास्तविक ₹3,78,262 करोड़ से काफी वृद्धि दर्शाता है।

* **2024-25 (वास्तविक):-** कुल व्यय ₹46,52,867, पूंजीगत व्यय (₹ करोड़) 10,51,953, राज्यों को हस्तांतरण (₹ करोड़) 3,78,262

* **2025-26 (आरई):-** कुल व्यय (₹ करोड़) 49,64,842, पूंजीगत व्यय (₹ करोड़) 10,95,755, राज्यों को हस्तांतरण (₹ करोड़) 25,43,769

* **2026-27 (बीई):-** कुल व्यय (₹ करोड़) 53,47,315, पूंजीगत व्यय (₹ करोड़) 12,21,821, राज्यों को हस्तांतरण (₹ करोड़) 25,43,769



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2026-27 के बजट पर एक विशेष सारगर्भित विश्लेषणात्मक आलेख

विकसित भारत की नींव रखने वाला साहसिक बजट

- डॉ. जयंतिलाल भंडारी

यूकॉन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह बजट आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत सुधारों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तीन कर्तव्यों पर बजट को आधारित किया है। इनमें उत्पादकता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना, लोगों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और सबका साथ, सबके विकास के मद्देनजर दृष्टांत सुधार के साथ प्राप्ति करना शामिल है। इस बजट में रिफॉर्ड पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। यद्यपि बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आयकर भरना आसान किया गया है। बजट के नए प्रावधानों से बुनियादी ढांचा, छोटे शहर, एमएसएमई, शिक्षा, पर्यटन और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के लिए रोजगार के व्यापक मौके बढेंगे। खास बात यह भी है कि आगामी वर्ष के बजट के तहत वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच सुझावपूर्ण संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और सात फीसदी से अधिक विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी है। गौरवलाभ है कि नए बजट के तहत वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चिता, भूराजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन के बीच अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत स्थिरता व दीर्घकालीन विकास की रणनीति के साथ घरेलू



मांग की मजबूती पर्यावरण नवाचार, उद्यमिता बुनियादी ढांचा, कृषि विकास, गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ मैनुफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) स्वदेशी प्रोत्साहन और हरित ऊर्जा पर बढ़े एलान किए हैं। इनके साथ-साथ भारत को वैश्विक बायो फार्मा केंद्र बनाने, शहरी आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण, नए राष्ट्रीय जल मार्ग, सात हाई स्पीड कोरिडोर, व्यापार सुगमता, कंटेनर निर्माण, बुक्यों के लिए मजबूत इकोसिस्टम, टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। निश्चित रूप से वित्त मंत्री इस बजट के माध्यम से युवाओं के रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। नए बजट में हर क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को अहमियत हेतु प्रावधान किए गए हैं, ताकि भारत एआई का वैश्विक हब बन सके। चूंकि इस समय चीन, पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश से भी देश की बाहरी सुरक्षा के खतरे बढ़े हैं, ऐसे में सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए बजट में अधिक धन का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में भारत को दुनिया के बाजार और अधिक प्रभावी रूप से जुड़ने और भारत को निर्यात का नया हब बनाने के लिए नई रणनीति प्रस्तुत की है। भारत को यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बाद दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को बूट करने के प्रोत्साहन मुक्त प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। इतना ही नहीं अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित निर्यात क्षेत्रों को भी राहत देने के मद्देनजर वित्त मंत्री नए निर्यात प्रोत्साहनों को डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने इस बजट में सीमा शुल्क के लिए जहां राहत दी है, वहीं सीमा शुल्क में सुधार भी किए हैं। निश्चित रूप से वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत बजट कोई साधारण वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट देश के आर्थिक परिदृश्य को ऐतिहासिक मोड़ देने वाला बजट है। उम्मीद करें कि इस बजट से जहाँ देश में साहसिक सुधारों को नया युग शुरू होगा, वहीं आम आदमी के लिए अधिक राहत और देश के लिए तेज विकास का नया परिदृश्य निमित्त होगा। उम्मीद करें कि एक ओर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 के बजट के बजट के लक्ष्य के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक रखने में कामयाब होंगे। उम्मीद करें कि इस अभूतपूर्व बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

बजट 2026: सरकार का बड़ा फैसला अब अनजाने में टैक्स छिपाने पर नहीं होगी जेल

संजय कुमार बाटला

बजट 2026: सरकार का बड़ा फैसला, अब अनजाने में टैक्स छिपाने पर नहीं होगी जेल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया। उन्होंने इनकम टैक्स में सुधार का एलान किया। सरकार ने कहा कि अब करदाता को अपराधी की नजर से नहीं देखा जाएगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश देश में भरोसा आधारित टैक्स संरचना विकसित करना है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी की आय में कोई गड़बड़ी मिलती है या अनजाने में टैक्स छिपाया जाता है तो सजा की बजाय केवल जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, जिन लोगों की विदेशों में अधोषि्ट संपत्तियां हैं, उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 6 महीने का विशेष समय मिलेगा। वह लोग एक खास प्रकटीकरण स्कीम के तहत अपने संपत्ति की जानकारी देकर कानूनी दांवपेचों से बच सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट 2026-27 के भाषण में कहा, “छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा। शेष अभियोगों को अपराधी की गंभीरता के अनुरूप वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा।” वित्त मंत्री के कहे, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए करदाता पर जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे अपील प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो। इसके अलावा, अग्रिम भुगतान की राशि को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है और इसकी गणना केवल मूल कर मांग पर ही की जाएगी। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में बड़ी राहत दी है। अब आईटीआर में गलती होने पर इसे सुधारना आसान होगा और इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त समय देने का एलान किया है। अब करदाता मामूली फीस दे रिटर्न को अपेट कर संकेगा। सरकार ने प्रांटी खरीदने को भी आसान बना दिया है। अगर आप किसी एनआरआई से घर या जमीन खरीदते हैं तो पहले की तरह टैन नंबर की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और बिना टैन के भी टीडीएस कट संकेगा। वहीं, अब छोटे करदाताओं को निल टीडीएस के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और पूरी प्रक्रिया अब ऑटोमैटिक और डिजिटल हो जाएगी।

बजट 2026 में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और जरूरी कदम।

पिकी कुंडू

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि देश के हर जिले में एक Girls Hostel बनाया जाएगा। यह सिरफ़ इमारत नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए सुरक्षित ठिकाना होगा जो पढ़ाई, नौकरी और आत्मनिर्भर बनने का सपना लेकर घर से बाहर निकलती हैं। यह फैसला शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर — तीनों को एक साथ मजबूत करता है। बजट 2026 में सशक्त भारत की नींव, बेटियों के सुरक्षित भविष्य से रखी जा रही है।

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए देश के हर जिले में होगा एक Girls Hostel!

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण



समय से पहले रेट बढ़ाकर सिगरेट और पान मसाले के खरबो रुपये कमाये किसी भी विभाग या संबंधित ने सुध नहीं ली जनता को लुटवाया



संजय कुमार बाटला

सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि 1 फरवरी 2026 से सिगरेट की कीमतें बढ़ गई हैं। सरकार ने सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे कीमतें लगभग 15% से 40% तक बढ़ गई हैं।

- सिगरेट की नई कीमतें:
 - 10 रुपये वाली सिगरेट अब 14 रुपये तक हो सकती है।
 - 18 रुपये वाली सिगरेट अब 24 रुपये तक हो सकती है।
- तंबाकू उत्पादों पर बढ़ा शुल्क:
 - सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 200-735 रुपये प्रति 1,000 स्टिक से बढ़कर 2,700-11,000 रुपये हो गया है।
 - चबाने वाले तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़कर 100% हो गया है।
 - हुक्का तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़कर 40% हो गया है।
- गुटखा और पान मसाले पर 1 फरवरी 2026 से 40% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था। इसके अलावा, अतिरिक्त एक्ससाइज ड्यूटी और हेल्थ सेस भी लगेगा। इस बढ़े हुए टैक्स का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों की खपत को कम करना और सरकार के राजस्व में वृद्धि करना है।
- टैक्स दरें:
 - गुटखा और पान मसाले पर 40% जीएसटी
 - अतिरिक्त एक्ससाइज ड्यूटी और हेल्थ सेस - लागू होने की तिथि: 1 फरवरी 2026
 - उद्देश्य: तंबाकू उत्पादों की खपत को कम करना और सरकार के राजस्व में वृद्धि करना।



पिकी कुंडू

1. पृष्ठभूमि
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या केवल पुलिस अनुरोध पर बैंक ग्राहक खातों को फ्रीज कर सकते हैं।
- मामला एक मेडिकल स्टोर चेन की याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसका एक्सिस बैंक खाता राचकोडा पुलिस (हेदराबाद) द्वारा डेबिट फ्रीज नोटिस जारी करने के बाद फ्रीज कर दिया गया था।
- पुलिस ने आरोप लगाया कि साइबर अपराध पीड़ित के खाते से धोखाधड़ी से स्थानांतरित धनराशि याचिकाकर्ता के खाते में पहुँची थी।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

<https://tolwa.com/about.html>
tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार: “बैंक खाते फ्रीज करने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय”

2. न्यायालय की टिप्पणियाँ
- कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल पुलिस अनुरोध पर बैंक खाते फ्रीज नहीं कर सकते। उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
- नागरिक और आपराधिक दायित्व: यदि बैंक बिना विधिक प्रक्रिया के खाते फ्रीज करते हैं, तो उन पर नागरिक और आपराधिक दोनों प्रकार की कार्रवाई हो सकती है।
- पुलिस नोटिस की कमियाँ:

- एक्सिस बैंक को जारी नोटिस में फ्रीज की जाने वाली राशि का उल्लेख नहीं था।
- बार-बार अनुरोध के बावजूद जाँच अधिकारी ने एफआईआर की प्रति या औपचारिक जन्ती आदेश उपलब्ध नहीं कराया।

3. न्यायालय का निर्णय
- हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता का खाता डी-फ्रीज करने का आदेश दिया।
- साथ ही प्रक्रिया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए:

- खाते फ्रीज करने की सूचना तुरंत बैंक या भुगतान सेवा प्रणाली के नोडल अधिकारी को भेजी जाए।
- बैंक तभी कार्रवाई करें जब उचित कानूनी दस्तावेज (एफआईआर, जन्ती आदेश या न्यायिक निर्देश) प्रस्तुत हों।

4. निर्णय के प्रभाव
- बैंकों के लिए:

- खाते फ्रीज करने से पहले सावधानी



बरते और उचित दस्तावेज माँगें।
- अनुपालन न करने पर मुकदमेबाजी और दायित्व का सामना करना पड़ सकता है।
- पुलिस के लिए:

- जाँच अधिकारियों को सुनिश्चित

करना होगा कि नोटिस एनसीआरपी शिकायतों, एफआईआर, जन्ती आदेश या न्यायिक निर्देशों से समर्थित हों।
- अस्पष्ट या अधूरे नोटिस विधिक रूप से मान्य नहीं होंगे।
- नागरिकों के लिए:

- व्यक्तियों और संगठनों को मनमाने ढंग से खाते फ्रीज किए जाने से सुरक्षा मिलेगी।
- यदि विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं होता, तो वे अदालत में चुनौती दे सकते हैं।

5. व्यापक महत्व
- यह निर्णय वित्तीय जाँचों में विधिक प्रक्रिया की सुरक्षा को मजबूत करता है।
- यह साइबर अपराध मामलों में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

- यह कानून प्रवर्तन और वित्तीय संस्थाओं के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- 6. मुख्य निष्कर्ष**
 - नागरिक अल्पसंख्यक अनुरोध पर बैंक खाते फ्रीज नहीं कर सकते।
 - उचित कानूनी दस्तावेज अनिवार्य हैं।
 - मनमाना फ्रीज करना बैंकों के लिए नागरिक और आपराधिक दायित्व ला सकता है।
 - नागरिकों को अवैध खाते फ्रीज करने के विरुद्ध न्यायिक उपाय उपलब्ध हैं।
 - यह निर्णय साइबर अपराध से संबंधित वित्तीय जाँचों में प्रक्रिया की अखंडता को सुदृढ़ करता है।

धर्म अध्यात्म



साप्ताहिकी अंकशास्त्र



डॉ. पूजाप्रसन्न एन
गोविल मेहरिस्ट
09599101326, 07303855446

अंकशास्त्र के दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं — पिनैकल्स (Pinnacles) और चैलेंजिस (Challenges)।

जहाँ पिनैकल्स जीवन में मिलने वाले अवसर, उपलब्धियाँ और ऊँचाइयों को दर्शाते हैं, वहीं चैलेंजिस उन परीक्षाओं और बाधाओं का संकेत देते हैं जिनके माध्यम से आत्मा का विकास होता है। जीवन के चार अलग-अलग, क्रमबद्ध जीवन चक्रों (फेज) और उनसे जुड़े अवरोधों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और जीवन की प्रमुख थीम्स को परिभाषित करते हैं। पिनैकल्स जहाँ अवसरों और वातावरण (environmental atmosphere) को दर्शाते हैं, वहीं चैलेंजिस उन पाठों (Lessons) को दिखाते हैं जिन्हें पार करना आवश्यक होता है। ये चक्र सामान्यतः जन्मतिथि से गणना किए जाते हैं और व्यक्ति की प्रगति को दिशा देते हैं, जिनके परिवर्तन अक्सर जीवन में बड़े बदलाव लेकर आते हैं।

अंकशास्त्र में पिनैकल्स (Pinnacles) और चैलेंजिस (Challenges)

आपकी जीवन यात्रा का छिपा हुआ ब्लूप्रिंट (The Hidden Blueprint of Your Life's Journey) हर जीवन अध्यायो में खुलता है — अलग-अलग चरण, जो परिवर्तन, चुनौती, विकास और अवसर से चिह्नित होते हैं। फिर भी, कई लोगों के लिए ये परिवर्तन अचानक या बोझिल लगते हैं। अगर आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट्स के पीछे कोई गहरा पैटर्न हो तो? अंकशास्त्र इसी प्रश्न को कुंजी प्रदान करता है। इस प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के केंद्र में एक शक्तिशाली अवधारणा है —

पिनैकल्स साइकिल्स (Pinnacle Cycles):-
पिनैकल्स साइकिल्स क्या है?
ये चार प्रमुख जीवन काल, जो आपकी जन्मतिथि से निकाले जाते हैं, आपके भाग्य को चरणों में प्रकट होने का संकेत देते हैं। ये पारंपरिक अर्थों में भविष्यवाणी नहीं हैं, बल्कि ऊर्जात्मक थीम्स और आत्मा के आमंत्रण (soul invitations) हैं, जो समय के साथ आपके विकास का मार्गदर्शन करते हैं। हर पिनैकल्स साइकिल आपके व्यक्तिगत जीवन की पटकथा (Life script) का एक अध्याय होती है।
चार पिनैकल्स चक्र
पहला पिनैकल्स — आपके प्रारंभिक जीवन की नींव बनाता है। दूसरा पिनैकल्स — आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक विस्तार की ओर ले जाता है। तीसरा पिनैकल्स — आपको परिपक्व होने और अपने गहरे सत्य के साथ संरेखित होने की चुनौती देता है।

चौथा पिनैकल्स — समापन प्रदान करता है — आपकी विरासत, ज्ञान और संतुष्टि। पिनैकल्स साइकिल्स को समझने से आपको क्या स्पष्टता मिलती है? आपके जीवन के कुछ समय आसान और कुछ कठिन क्यों रहे? कब परिवर्तन शुरू करना चाहिए और कब स्थिर रहना चाहिए? आने वाले वर्षों में कौन-सी व्यक्तिगत थीम्स, सबक और अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं?
जीवन के चार मौसम और पिनैकल्स:-
पिनैकल्स जीवन के चार दीर्घकालिक चक्र होते हैं, जो जीवन के "मौसमों" का प्रतिनिधित्व करते हैं —
वसंत (Spring) — प्रारंभिक जीवन ग्रिष्म (Summer) शरद (Autumn) शीत (Winter) — वृद्धावस्था



4th Pinnacle (चौथा पिनैकल्स):-
यह व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि तक रहता है। यह चरण बुद्धिमत्ता, अनुभवों के एकीकरण और स्थिरता का होता है।
पिनैकल्स का महत्व (Significance):-
1. सफलता का रोडमैप पिनैकल्स यह मार्गदर्शन देते हैं कि: कब पहल करनी है कब नींव मजबूत करनी है और कब विस्तार करना है
2. थीम की पहचान अपने पिनैकल्स नंबर (1-9 या मास्टर नंबर) को जानकर, आप उस समय की ऊर्जा और वाइब को समझ सकते हैं।
उदाहरण:
1 (सूर्य) पिनैकल्स — स्वतंत्रता और नई शुरुआत।

6 (शुक्र) पिनैकल्स — परिवार, जिम्मेदारी और संबंधों पर फोकस।
अंकशास्त्र में चैलेंजिस (Numerology Challenges):-
चैलेंजिस नंबर वे विशेष, दोहराए जाने वाले अवरोध होते हैं, जिन्हें पार करना व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ये कोई नियत असफलताएँ नहीं हैं, बल्कि ऐसे जीवन पाठ हैं जो व्यक्ति को विशेष कौशल सिखाने के लिए बनाए गए हैं।

चार प्रकार के चैलेंजिस:-
पहला चैलेंजिस (प्रारंभिक):- जन्म से लगभग 30-35 वर्ष तक (जन्मतिथि पर निर्भर)।
दूसरा चैलेंजिस (मध्य):- इसको अवधि 9 वर्ष होती है।
तीसरा / मुख्य चैलेंजिस (मिड-लाइफ):- इसकी अवधि भी 9 वर्ष होती है। यह मध्य आयु में सबसे अधिक तीव्रता से महसूस होता है।
चौथा चैलेंजिस (अंतिम):- जीवन के उत्तरार्ध में और पूरे जीवनकाल तक गहराई से महसूस होता है।
चैलेंजिस का महत्व (Significance):-
कर्मिक सबक:- चैलेंजिस उन कमजोर क्षेत्रों या कर्मिक पाठों को उजागर करते हैं जिन्हें व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित करना आवश्यक होता है।
स्व-सुधार (Self-Correction) अपने चैलेंजिस नंबर को समझकर, व्यक्ति असुरक्षा, अधीरता, नियंत्रण की प्रवृत्ति जैसी आदतों पर

सचेत रूप से कार्य कर सकता है और अपनी उच्च क्षमता को खोल सकता है।
पिनैकल्स और चैलेंजिस: अंतर और समन्वय:-
पिनैकल्स = अवसर और वातावरण
→ आपको क्या अनुभव करना या प्राप्त करना है।
चैलेंजिस = बाधाएँ और चरित्र विकास → सफल होने के लिए आपको किन बातों पर काम करना है।
पिनैकल्स और चैलेंजिस का संयुक्त प्रभाव:-
यदि कोई पिनैकल्स नंबर चुनौतीपूर्ण या तीव्र है, तो संबंधित चैलेंजिस नंबर को समझकर उस पिनैकल्स को काफ़ी सहजता से जिया जा सकता है। इससे जीवन अधिक सचेत और सक्रिय बनता है। जब हम केवल पिनैकल्स देखते हैं, तो हमें अवसर दिखाते हैं, जो केवल चैलेंजिस देखते हैं, तो कठिनाईयाँ दिखती हैं। लेकिन दोनों को साथ समझने से जीवन का वास्तविक रोडमैप स्पष्ट होता है: → उच्च पिनैकल्स + कठिन चैलेंजिस = महान उपलब्धियाँ लेकिन कठिन संघर्ष।

साधारण पिनैकल्स + हल्के चैलेंजिस = स्थिर, शांत और संतुलित जीवन।
यदि पिनैकल्स अनुकूल हो लेकिन जीवन कठिन लगे तो क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति अपना चैलेंजिस ऑनोवर्ड कर रहा होता है। अंकशास्त्र कहता है — जब तक चैलेंजिस स्वीकार नहीं किया जाता, पिनैकल्स का प्रभु फल नहीं मिलता।
उदाहरण:-
यदि आप 6 पिनैकल्स (जिम्मेदारी और

परिवार पर फोकस) में हैं और साथ ही 6 चैलेंजिस भी चल रहा है, तो आपको जिम्मेदारियों के अत्यधिक बोझ महसूस हो सकता है। यहाँ जीवन का सबक है — सिर्फ बोझ उठाना नहीं, बल्कि संतुलन सीखना।
यह क्यों महत्वपूर्ण है? (Why This Matters?):-
अधिकोश लोग जीवन में उन पवित्र लयों (sacred rhythms) से अनजान रहते हैं जो ऊर्हें दिशा दे रही होती हैं। लेकिन जब आप अपने पिनैकल्स साइकिल्स और आने वाले चैलेंजिस को समझ लेते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं है — हर अनुभव के पीछे एक देवी बुद्धि (divine intelligence) कार्य कर रही है।

यह ज्ञान आपको:-
आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने बेहतर निर्णय लेने और अपने जीवन के सही समय का सम्मान करने की शक्ति देता है। आप अपनी योजनाओं के साथ पहले से तैयार रहते हैं, अपनी क्षमता और चुनौतियों से अवगत होते हैं, और इसी कारण वर्तमान जीवन परिस्थितियों में सही कदम उठाकर सफलता की यात्रा सहजता से तय कर पाते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion):-
पिनैकल्स हमें बताते हैं कहाँ पहुँचना है, चैलेंजिस बताते हैं कैसे पहुँचना है। अंकशास्त्र में यही संतुलन जीवन को दिशा देता है। जो व्यक्ति अपने पिनैकल्स और चैलेंजिस को समझकर जीवन जीता है, वह भाग्य का मोहताज नहीं रहता, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है।



पिकी कुंडू

चण्डी पाठ किए बिना भी वही फल सिद्धकुंजिकास्तोत्र

सिद्धकुंजिकास्तोत्र केवल एक स्तोत्र नहीं है, बल्कि शक्ति-साधना की वह कुंजी है, जो दुर्गा सप्तशती के गूढ़ द्वार खोल देती है। "सिद्ध" यानी सिद्धि देने वाला और "कुंजिका" यानी ताला खोलने वाली चाबी — नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जब यह समझ में आता है, तो एहसास होता है कि यह स्तोत्र वास्तव में सप्तशती का संक्षिप्त सार है। पौराणिक कथा कहती है कि एक बार माता पार्वती के मन में भी वही प्रश्न उठा, जो आज कई साधकों के मन में आता है — इतना विस्तृत चण्डी पाठ, क्या इसका कोई सरल रहस्य नहीं? तब भगवान शिव ने यह गुप्त स्तोत्र प्रदान किया। उनका कथन सीधा और स्पष्ट था — जो इसे श्रद्धा से जपता है, वह संपूर्ण सप्तशती का फल पा लेता है। इस स्तोत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह कम शब्दों में अधिक शक्ति समेटे हुए है। सात सौ श्लोकों का भाव, बीस मंत्रों की ऊर्जा, कवच की सुरक्षा और कीलक-अर्गला की गहराई — सब कुछ इसमें अंतर्निहित है। यही कारण है कि व्यस्त जीवन जीने वाले गृहस्थों से लेकर गूढ़ तांत्रिक साधक तक, सभी के लिए इसका महत्व समान रूप से बढ़ जाता है। सिद्धकुंजिकास्तोत्र का प्रभाव केवल बाहरी रक्षा तक सीमित नहीं है। यह भीतर से मन को स्थिर करता है, भय को शांत करता है और आत्मबल



को जगाता है। इसमें नवदुर्गा की करुणा भी है और दश महाविद्याओं का सूक्ष्म स्पर्श भी। यह आकर्षण या वशीकरण की बात नहीं करता, बल्कि भीतर छिपे तेज और साहस को जागृत करता है। पाठ की विधि भी जटिल नहीं है — बस भाव शुद्ध हो। नवरात्रि, विशेषकर गुप्त नवरात्रि, इसका समय और भी प्रभावशाली बना देती है। एक दीपक, एक आसन और शांत मन — इतना ही पर्याप्त है। गुरु के बिना भी इसका पाठ किया जा सकता है, यदि श्रद्धा और मर्यादा बनी रहे। नियमित पाठ करने वालों का अनुभव अक्सर एक जैसा होता है — जीवन की अदृश्य बाधाएँ धीरे-धीरे हटने लगती हैं, मन में अकारण स्थिरता आती है और माँ दुर्गा की उपस्थिति केवल विश्वास नहीं, अनुभूति बन जाती है। शायद यही कारण है कि इसे "कुंजी" कहा गया है — क्योंकि यह बाहर नहीं, अंदर का द्वार खोलती है।

सृष्टि में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है

एक बार स्वर्ग लोक में देवताओं के बीच चर्चा छिड़ी कि सृष्टि में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है। कोई ज्ञान को बड़ा कहता, तो कोई पराक्रम को तभी देवीर्षि नारद ने सुझाव दिया कि इस प्रश्न का उत्तर केवल कैलाश पर ही मिल सकता है। जब सभी देवता कैलाश पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड शांत है और भगवान शिव अपनी आँखें बंद किए ध्यान मग्न हैं। माता पार्वती उनके समीप ही बैठी थीं। नारद मुनि के अनुरोध पर शिव जी ने अपनी आँखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति के बिना शिव शिव है, और शिव के बिना शक्ति का कोई आधार नहीं। सृष्टि का आधार केवल इन दोनों का संतुलन है।

इसे सिद्ध करने के लिए शिव और शक्ति ने नृत्य आरंभ किया। * भगवान शिव ने 'तांडव' नृत्य शुरू किया, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा, विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। * उनके हर कदम से धरती और आकाश गुंजन लगे। * शिव के उग्र नृत्य को संतुलित करने के लिए माता पार्वती ने अत्यंत कोमल और सुंदर 'लार्य' नृत्य किया। * उनके नृत्य में प्रेम, सृजन और ममता की झलक थी। * जैसे-जैसे नृत्य आगे बढ़ा, शिव और शक्ति एक-दूसरे की गति में समाहित हो गए। * यह नृत्य देख देवता समझ गए कि संसार केवल युद्ध या केवल शांति से नहीं, बल्कि दोनों के सुंदर तालमेल से चलता है।



नारद का अहंकार

पिकी कुंडू
एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्रीराम के द्वार पर पहुँचे। नारायण नारायण !! नारदजी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जो पहरा दे रहे है। हनुमान जी ने पूछा: नारद मुनि! कहीं जा रहे हो? नारदजी बोले: मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारदजी ने हनुमानजी से पूछा प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमानजी बोले: पता नहीं पर कुछ बही खाते का काम कर रहे है, प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे है। नारदजी: अच्छा? क्या लिखा पढ़ी कर रहे है? हनुमानजी बोले: मुझे पता नहीं मुनिवर आप खुद ही देख आना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे है। नारद जी बोले: प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं? ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले: नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी: अच्छा प्रभु ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले: तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले: नही प्रभु बताइये ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले: नारद इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल भजते हैं। मैं उनको नित्य हाजिरी लगाता हूँ।

नारद जी: अच्छा प्रभु जरा बताइये तो मेरा नाम कहीं पर है? नारदमुनि ने बही खाते को खोल कर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है? नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्रीराम जी के खास भक्त है फिर उनका नाम, इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि आये हनुमान जी के पास बोले: हनुमान! प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं पर आप का नाम उस में कहीं नहीं है? हनुमान जी ने कहा: मुनिवर! होगा, आप ने शायद ठीक से नहीं देखा होगा? नारदजी बोले: नहीं नहीं मैंने ध्यान से देखा पर आप का नाम कहीं नहीं था। अगर आपको कथा संग्रह की पोस्ट पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें कथा संग्रह हनुमानजी ने कहा: अच्छा कोई बात नहीं। शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाये। पर नारद जी प्रभु एक अन्य दैनिकी भी रखते हैं उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारदजी बोले: अच्छा?



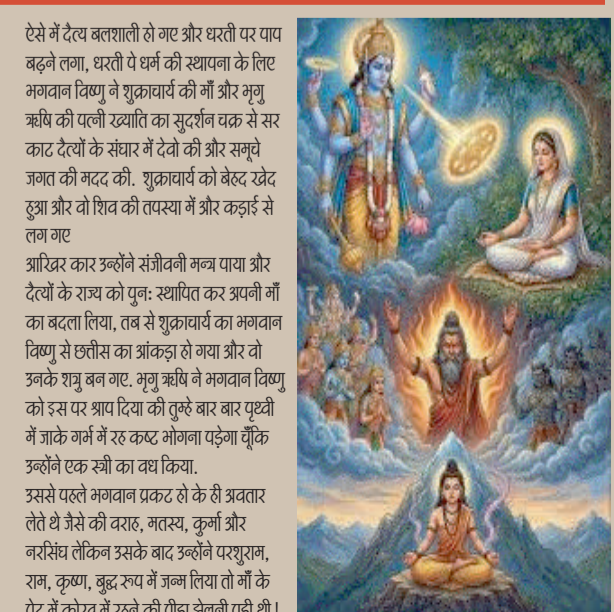
नारदमुनि ने कहा: हाँ! नारदमुनि फिर गये प्रभु श्रीराम के पास और बोले प्रभु! सुना है कि आप अपनी अलग से दैनिकी भी रखते है! उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्रीराम बोले: हाँ! पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारदजी: प्रभु! बताइये, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं? प्रभु मुस्कुराये और बोले: मुनिवर मैं इन उन भक्तों के नाम लिखता हूँ

जिन को मैं नित्य भजता हूँ। नारदजी ने हाथरी खोल कर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देख कर नारदजी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जीव्हा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं।

भगवान विष्णु ने मारा था शुक्राचार्य की माँ को, बदले की भावना में बने दैत्यगुरु!

पिकी कुंडू
शुक्राचार्य का नाम तो सबने सुना ही होगा, इतना सबको पता है की वो देवों और राक्षसों के गुरु थे लेकिन वे कोई नली जानता होगा की वो कौन थे कहां से आये थे, आयको बताते है उनके ऋषि थे देवगुरु होने की कथा. संत मनु जिन्होंने अपनी देवी वाली पत्नी को अपनी आँखें डेके फिर जीवित किया। नदब्राह्मों में शुमार शुक्र ही शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ मनु ऋषि के पुत्र है मनु ऋषि जिन्हें धरती के सब ऋषियों ने तैनी देवो (ब्रह्मा दिव्य गुरु) में कौन सर्वश्रेष्ठ है ज्ञानके की निम्नोदारी. ऐसे पत्नीय ऋषि का पुत्र लेके भी शुक्राचार्य देवों के गुरु कैसे बन गए. बाद बहुत पुरानी है मनु ऋषि की दो पत्निया थी पहली दक्ष की कन्या थी और दूसरी ही ख्याति निम्नो उल्लेख पुत्र मित्रा शुक्राचार्य. उनके नाम पे ही शुक्र का नाम शुक्राचार्य पड़ा, पिता ने उन्हें ब्रह्मऋषि अंगिरा के पास शिक्षा के लिए भेजा. गर्भतीनी का राक्षस ने किया उत्पीड़न तो समय से पहले देहा देव्यवन। अंगीरीशी ब्रह्मा के गान्धस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे, शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति (जो बाद में देवों के गुरु बने) भी पढ़ते थे. शुक्राचार्य बृहस्पति की तुलना में काष्ठी लेशियार थे, लेकिन फिर भी बृहस्पति को पुत्र लेने के वक्तें शुक्र को ज्यादा श्रेष्ठी तरह से शिक्षा नही मिली. र्ख्या करा वो उस से दीक्षा छोड़ के सबक ऋषियों और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे. इस दौरान उन्हें प्रेरणा मिली और जब बृहस्पति देवों के गुरु बने तो र्ख्या वय वो देवों के गुरु बने. देव देवों से भित सरते थे इसलिए उन्होंने (शुक्राचार्य) शिव को परब्रह्म संजीवनी नव्य (भरे हुए को जीवित करने का नव्य) हेतु तपस्य में बैठ गए. लेकिन देवों वे मोके का फायदा उठा के देवों का संघार आरम्भ कर दिए, शुक्राचार्य को तपस्य में जान देव्य उनकी नाता ख्याति की शरण में वले गए. ख्याति ने देवों को शरण दी और जो भी देवता देवों को मारने आता वो उसे मुर्खित कर देती या अपनी शक्ति से तलकवाबस्त.

देसे में देव्य बलशाली ले गए और धरती पर पाय बढ़ने लगा, धरती पे घर्भ की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को गौरी और अनु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदुर्शन वक से सर काट देवों के संघार में देवों की और समूह जगत की बदद की. शुक्राचार्य को बेदद खेद हुआ और वो शिव की तपस्य में और कड़ाई से लगे गए आश्रित कर उन्होंने संजीवनी नव्य पाया और देवों के राक्ष को पुनः स्थापित कर अपनी माँ का बदला लिया, तब से शुक्राचार्य का भगवान विष्णु से छीसी का प्रकटन ले गया और वो उनके शत्रु बन गए. मनु ऋषि ने भगवान विष्णु को इस पर श्राप दिया की तुम्हें बार बार पृथ्वी में जाके गर्भ में रह करद भोगना पड़ेगा और उन्हें एक स्त्री का वध किया. उससे पहले भगवान कण्ट से के ले श्रवता लेते थे जैसे की वरह, प्रतस्य, कुर्मा और नरशिखर लेकिन उसके बाद उन्होंने परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध वगैरे में लब्ध किया तो भी के पेट में कोरछ में रखे की पीडा जेतनी पड़ी थी।



जब संत मार्गदर्शन करते हैं तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता: बेदी



225 बेड का आयुर्वेद चिकित्सालय मानवता की सेवा का बनेगा मंदिर बोले -- कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी

परिवहन विशेष न्यूज

इज्जर, 1 फरवरी। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने रविवार को गांव माजरा दबूलखन स्थित तपोभूमि जटला धाम स्वामी नितानंद जी महाराज के आश्रम में आयोजित पूर्णिमा महोत्सव एवं सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री बेदी ने उपस्थित जनों को पूर्णिमा दिवस तथा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामी नितानंद जी का यह धाम अध्यात्मिक चेतना से जोड़ता है। जटला धाम की यह पवित्र तपोभूमि संतों के आशीर्वाद से अध्यात्मिक केंद्र के रूप में पहचान स्थापित कर रही है।

उन्होंने कहा कि जब संत मार्गदर्शन करते हैं तो समाज सही दिशा में चलता है और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। स्वामी नितानंद जी महाराज जैसे महान संतों की बदौलत ही मजबूत भारत हमें मिला है। उन्होंने कहा कि स्वामी नितानंद महाराज जी के जीवन मूल्यों को धारण करते हुए समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए। स्वामी नितानंद मिशन फाउंडेशन समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के मिशन में निरंतर कार्य कर रहा है।

मानवता की सेवा का आश्रम बनेगा चिकित्सा संस्थान

कैबिनेट मंत्री श्री बेदी ने कहा कि स्वामी नितानंद मिशन फाउंडेशन के सान्निध्य में बन रहा यह 225 बेड का आयुर्वेद चिकित्सालय मानवता की सेवा का एक मंदिर है। इस संस्थान के बनने के बाद क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस संस्थान से इज्जर ही नहीं बल्कि साथ लगते क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हमारी सरकार निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रही है। हर जिले में

आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल होगा। इस दौरान उन्होंने इस नए कार्य में अपना तन मन धन से योगदान देने वालों को सम्मानित किया।

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जटला धाम समाज कल्याण कि दिशा में लगातार कार्य किए जा रहा है। सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए ए प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए धाम द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वामी नितानंद जी एक महान संत थे जिनकी वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का महान कार्य जटला धाम के महंत स्वामी राजेंद्र दास द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने निर्माणधीन आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।

संतों के मार्ग पर चलकर जीवन को सफल बनाएं नागरिक: राजेंद्र दास जी महाराज

महंत राजेंद्र दास महाराज जी ने कहा कि स्वामी नितानंद एक महान स्तंभ थे जो समाज को प्रेरणा देता है। ऐसे सत अच्छे विचार देते हैं जिन पर चलते हुए समाज आगे बढ़ता है।

उन्होंने कहा कि मानव देह संत की अपार कृपा से मिलती है। जन्म के बाद मनुष्य अशुभ कार्यों में लग जाता है जो कि अपने ही बुरे कर्म बना रहा है जिसके परिणाम भी बहुत ही गलत होंगे। उन्होंने कहा कि संतों के दिखाए मार्ग पर चलकर ही इस जीवन को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर संत नहीं होते तो समाज आज इतने बेहतर स्वरूप में नहीं होता। बेहतर समाज के निर्माण में संतों की अहम भूमिका है।

श्री राजेंद्र दास महाराज जी ने कहा कि हमारी संगत ने एक साल में लगभग एक साल में एक लाख से ज्यादा पेड़ पौधेवाण संरक्षण में कदम बढ़ाते हुए लगाए हैं।

उन्होंने बताया कि चिकित्सा संस्थान आयुर्वेद शोध और उसके नवाचार के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित होगा। यहां पर आयुर्वेदिक पद्धति को नई तकनीक के साथ चिकित्सीय सेवा में बदलने का लिए समाज-कल्याण का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि संलग्न अग्रवाल महेंद्राछ ने अस्पताल के में लगने वाली सभी कंक्र्रीट (रेती, रोड़ी बजरी

आदि) सेवा हेतु उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाखों दानदाताओं द्वारा इस अस्पताल के निर्माण हेतु दान दिया जा रहा है।

समारोह में योगमान्य व्यक्तित्व रहे मौजूद

सुखासा महाराज रोहतक, संत शुभाराम कोटेश्वर, राकेश कादयान सीजेएम गुरुग्राम, गोपालिका बेरी के चैयरमैन देवेन्द्र कादयान, मार्केट कमिटी बेरी के चैयरमैन राजेंद्र शर्मा, प्रोफेसर अजय कादयान व यशवीर वत्स, रिटायर्ड डीईओ ओमप्रकाश कादयान, ब्लॉक समिति मेंबर सूरजमल कौशिक, माजरा बी से सरपंच प्रतिनिधि नीरज, सरपंच विनोद कुमार माजरा डी, मास्टर चांद, ग्राम पंचायत वेलरखां से सरपंच पृथ्वी सिंह, डाबीटिक सिंह गांव से सरपंच वीरेंद्र सिंह, पदार्थखेड़ा के सरपंच मनेजर सिंह तथा रेवर गांव के सरपंच ओमप्रकाश तथा प्रशासनिक तौर पर रेणुका नांदल एसडीएम बेरी, एसपी बेरी अनिल कुमार, नायब तहसिलदार सुरेंद्र कुमार, एसएचओ विकास सुमार सहित हजारों की संख्या में संगत उपस्थित रही।

रोहिणी में विराट हिंदू सम्मेलन भव्यता के साथ संपन्न



नई दिल्ली, 1 फरवरी। हिंदू समाज को संगठित करने, उसकी परंपराओं, संस्कृति एवं मूल्यों के संरक्षण के उद्देश्य से रोहिणी स्थित रामलीला मैदान में एक भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में जनसमुदाय की उपस्थिति रही और सामाजिक एकता, स्वच्छता तथा राष्ट्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

कार्यक्रम में मंचासीन विशिष्ट अतिथियों में प्रसिद्ध कथावाचक नवल किशोर जी महाराज, राम निवास यादव (सेवा निवृत्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा गौरव से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सविता चड्ढा तथा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख नेता फैज खान उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में संघ प्रचारक अजय जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक भूमिका और राष्ट्र

निर्माण में उसके योगदान पर अपने विचार रखे। सम्मेलन में सभी माननीय अतिथियों का सम्मान पीली पगड़ी, अंगवस्त्र एवं "विशिष्ट प्रतिभा सम्मान प्रतीक" प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ, जिसके पश्चात रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य-नाटिका तथा विभिन्न सम्मान समारोह आयोजित किए गए। इस अवसर पर

चड्ढा ने अपने उद्घोषण में कहा कि इस सम्मेलन में सहभागिता उनके लिए नए जन्म के समान है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का पुनर्जन्म केवल शारीरिक नहीं, बल्कि चिंतन में नवीनता के प्रवेश से भी होता है। अपने संबोधन में उन्होंने महिलाओं की भूमिका और समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। सम्मेलन का कुशल एवं प्रभावी संचालन निकुंज शर्मा ने किया। सम्मेलन की आयोजन समिति में हेरीश जी, भूपेंद्र शर्मा, राजेश गोयल, कपिल शर्मा, सुरेश कुमार एवं विनीत अग्रवाल प्रमुख रूप से शामिल रहे। आयोजकों ने उपस्थित जनमानस को समाज में एकता, स्वच्छता अभियान तथा विभिन्न राष्ट्रीय विकास योजनाओं की जानकारी दी।

संपूर्ण आयोजन अनुशासित, गरिमापूर्ण और सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला रहा।

एक मजबूत, गरिमामय और सशक्त बार काउंसिल की स्थापना के लिए शाहिद अली एडवोकेट का व्यापक विज्ञान

शम्सआगाज

नई दिल्ली: एडवोकेट समुदाय की समग्र भलाई, पेशेवर सुरक्षा और संस्थागत सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाहिद अली एडवोकेट ने एक व्यापक, दूरदर्शी और सुधारोन्मुखी विज्ञान प्रस्तुत किया है। इस विज्ञान का मूल लक्ष्य ऐसी बार का निर्माण है जो न केवल युवा वकीलों का संरक्षण करे, बल्कि वरिष्ठ वकीलों के अनुभव, सेवाओं और गरिमा का भी पूर्ण सम्मान करे, और प्रत्येक वकील के जीवन, संपत्ति, सम्मान तथा पेशेवर स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

शाहिद अली द्वारा प्रस्तुत विज्ञान में नवीन वकीलों को दूरदर्श आर्थिक चुनौतियों को समझते हुए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रस्ताव शामिल है। इसके तहत वकीलों के शुरुआती तीन वर्षों में युवा वकीलों को प्रतिमाह 15,000 रुपये का वजीफा प्रदान करने की बात

पुरुष सेपक टेकराव ने टोक्यो में आयोजित एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम किया रौशन



लोकप्रियता का नया-नया मुकाम बना रही है। उन्होंने कहा कि देश में भी यह खेल काफी लोकप्रिय हो रहा है और युवा भारी संख्या में इस खेल से जुड़ रहे हैं।

कौन-कौन आते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के दायरे में



नरेश गुणपाल

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 2(एच) में यह प्रावधान किया गया है कि कौन-कौन से विभाग, संस्थान या निकाय इस कानून के दायरे में आते हैं। इन्हें अधिनियम में रलोक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) कहा गया है।

ये संस्थान जन सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के दायरे में आते हैं :-

- संवैधानिक और वैधानिक निकाय (कंस्यूट्रिशनल एवं स्टेटरी बॉडीज) :- वे सभी संस्थाएं जिनका गठन निम्न तरीकों से हुआ है :-
- डु संविधान के तहत (जैसे- चुनाव आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, यूपीएससी, कैग आदि)।
- डु संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत (जैसे- केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेबी, एलआईसी आदि)।
- डु राज्य विधानसभा/विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत (जैसे- राज्य परिवहन निगम, राज्य विश्वविद्यालय आदि)।
- सरकारी आदेश / अधिसूचना द्वारा स्थापित/ गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था।
- सरकार द्वारा वित्त पोषित (फाइनेंस) संस्थाएं।

इसमें दो महत्वपूर्ण श्रेणियां शामिल हैं : स्वामित्व या नियंत्रण -

ऐसी संस्थाएं /निकाय जिनका स्वामित्व सरकार के पास है या जिन पर सरकार का नियंत्रण है।

वित्त पोषित: ऐसी संस्थाएं, जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित हैं।

4. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) -वे सभी स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) भी जन सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं, जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित हैं।

क्या प्राइवेट (निजी) संस्थाओं पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू होता है? आमतौर पर निजी संस्थाएं/फर्म/ कंपनियां आदि सीधे तौर पर सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आती हैं।

अपवाद:- धारा 2(एच) के तहत, यदि किसी निजी संस्था की जानकारी किसी रलोक प्राधिकारी (सरकारी विभाग) के पास उपलब्ध है या कानून वही विभाग उस जानकारी को निजी संस्था से मांग सकता है, तो आप उस सरकारी विभाग के माध्यम से निजी संस्था की वह जानकारी मांग सकते हैं।

संक्षेप में, हर वह दफ्तर, निकाय, स्वायत्त संस्था, संस्थान जो सरकारी है या सरकारी वित्त पोषण से चलता है या सरकारी कानून से बना है, उन पर जन सूचना अधिकार अधिनियम लागू होता है।

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष सेपक टेकराव टीम ने मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों 2026 के टेस्ट इवेंट में टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता। टीम को मुख्य कोच हेमराज द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया और सेपक टेकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री नरेश कुमार द्वारा कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया। स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में आकाश युमनाम, संदीप कुमार, अरुण, राम कुमार, बाबी कुमार और एस मालमगबा सिंह शामिल थे, जिनके सामूहिक प्रयास और समर्पण ने देश को गौरव दिलाया। प्यह उल्लेखनीय उपलब्धि भारतीय सेपकटेकरा के

डॉ. जितेंद्र सिंह की दो कविताएँ साझा काव्य-संग्रह में शामिल

डॉ. शंभु पंवार

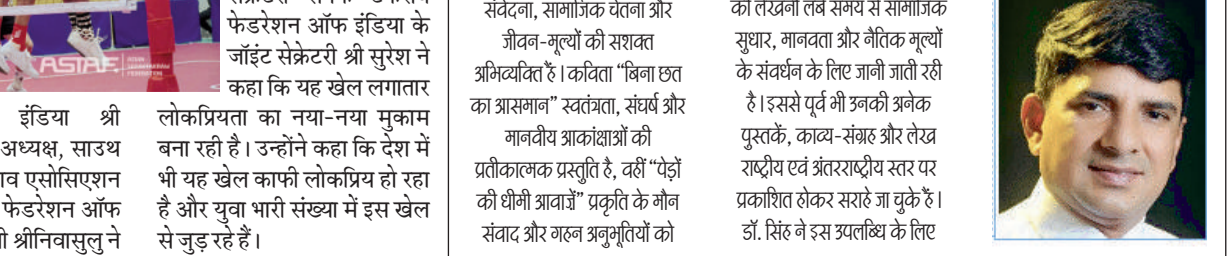
नई दिल्ली, 1 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय रचावित्पाठ लेखक, कवि एवं सामाजिक चिंतक डॉ. जितेंद्र सिंह की दो महत्वपूर्ण कविताएँ गुंबई से प्रकाशित साझा काव्य-संग्रह "लोकप्रिय हिंदी कविताएँ" में व्यक्ति लेखक प्रकाशित हुईं। इन कविताओं के शीर्षक हैं -- "बिना छत का आसमान" तथा "पेड़ों की धीमी आवाजें"।

डॉ. सिंह की रचनाएँ मानवीय संवेदना, सामाजिक चेतना और जीवन-मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। कविता "बिना छत का आसमान" स्वतंत्रता, संघर्ष और मानवीय आकाशों की प्रतीकात्मक प्रस्तुति है, वहीं "पेड़ों की धीमी आवाजें" प्रकृति के गहन संवाद और गहन अनुभूतियों को शब्द देती है।

यह साझा काव्य-संग्रह गुंबई स्थित इंक्लाव पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के चर्चित और अमरते रचनाकारों की कविताएँ संकलित की गई हैं। इस संग्रह में डॉ. जितेंद्र सिंह की रचनाओं का दायन प्रकृती साहित्यिक प्रतिभा, रचनात्मक दृष्टि और सामाजिक संरोकारों की व्यापक स्वीकृति को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि डॉ. जितेंद्र सिंह की लेखनी लंबे समय से सामाजिक सुधार, मानवता और नैतिक मूल्यों के संरक्षक के लिए जाती प्रतीत रही है। इससे पूर्व भी उनकी अनेक पुस्तकें, काव्य-संग्रह और लेख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होकर सराहें जा चुके हैं। डॉ. सिंह ने इस उपलब्धि के लिए

इंक्लाव पब्लिकेशन, गुंबई के प्रकाशक एवं संपादक मंडल का आभार व्यक्त करने के साथ ही उन्होंने सभी सह-रचनाकारों और पाठकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की, जिनके सखीय और रथ से यह साहित्यिक यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है।

डॉ. शंभु पंवार (वर्ल्ड रिकॉर्ड लेखक-अंतरराष्ट्रीय लेखक, पत्रकार-विवारक)



इंफाल मार्च का मजबूत संदेश: लोगों ने केंद्र से मणिपुर की सीमाओं की सुरक्षा की मांग की

संगिनी घोष,

मणिपुर की राजधानी इंफाल में इस सप्ताह हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार से राज्य की वर्तमान सीमाओं की रक्षा करने की मांग की। यह शांतिपूर्ण मार्च उन बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है, जो लोगों के मन में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर हैं।

छात्रों से लेकर स्थानीय नागरिकों तक, बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मणिपुर की सीमाएं केवल नक्शों की रेखाएं नहीं हैं, बल्कि यह राज्य की पहचान, सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा विषय है।

लोगों ने केंद्र सरकार से साफ आश्वासन मांगा कि कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा जो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करे।

इंफाल फोकस: शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन गंभीर चिंता



मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और शहर के प्रमुख इलाकों में पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। हालांकि प्रदर्शन का संदेश काफी स्पष्ट और मजबूत था।

कई लोगों ने कहा कि चिल रही राजनीतिक चर्चाओं और अनिश्चितता के कारण यह डर बढ़ रहा है कि कहीं राज्य की वर्तमान संरचना में बदलाव न किया जाए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, मणिपुर की सीमाओं की रक्षा करना जरूरी है ताकि पहले से संवेदनशील हालात और नबिगुं।

मणिपुर में यह मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है? मणिपुर पिछले कुछ वर्षों में तनाव और सामाजिक

अशांति का सामना करता रहा है। ऐसे में भूमि, पहचान और प्रशासन से जुड़े सवाल बेहद संवेदनशील बन जाते हैं।

इसी कारण सीमाओं में बदलाव की आशंका भी स्थानीय समुदायों के लिए भावनात्मक मुद्दा बन जाती है। मेरे अनुसार, इस बड़े मार्च से यह साफ है कि लोग शांति चाहते हैं, लेकिन साथ ही वे चाहते हैं कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए।

मुख्य बिंदु
स्थान: इंफाल, मणिपुर
घटना: हजारों लोगों का शांतिपूर्ण मार्च
मुख्य मांग: मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा

जनता की चिंता: राजनीतिक घटनाक्रमों से बढ़ती अनिश्चितता
सुरक्षा व्यवस्था: कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात
संदेश: मणिपुर की मौजूदा सीमाओं से कोई समझौता नहीं

राष्ट्रीय असर और आगे की राह
इस तरह के बड़े जन-आंदोलन यह दिखाते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार पर अब दबाव बढ़ेगा कि वह स्पष्ट जवाब दे और स्थानीय समुदायों से संवाद बढ़ाए, ताकि आगे किसी तरह की अशांति न फैले।

आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।
डिजिटल मेटा डिस्कशन (SEO):
इंफाल में हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर केंद्र सरकार से मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की मांग की। यह प्रदर्शन राजनीतिक घटनाक्रमों और राज्य की मौजूदा सीमाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है।

बजट 2026 से विकसित भारत की नींव मजबूत, गरीब-युवा-महिला सशक्त : दिलीप देवतवाल

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली। मदनगिर मंडल कार्यालय स्थित ब्यू स्टार हॉल, डीडीए फ्लैट मदनगिर में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर एक प्रभावशाली एवं राजनीतिक रूप से अहम प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष दिलीप देवतवाल ने किया। आयोजन में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सरकार की दूरदर्शी सोच और जनकल्याणकारी नीतियों को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम का शुरुआत संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए की गई। इस दौरान सामाजिक समरसता, समानता और श्रम सम्मान के मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में निगम प्रयाशी मनीषा बैरवा जी की विशेष उपस्थिति रही, जबकि मुख्य वक्ता नवीन गुप्ता ने बजट के प्रावधानों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ विस्तार से रखते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत@2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है।

मुख्य वक्ता नवीन गुप्ता ने बताया कि बजट देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ₹11 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान कर विकसित भारत के लिए आधुनिक सड़क, आवास और शहरी ढांचे को गति दी गई है। शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹1.20 लाख करोड़ से अधिक का बजट युवाओं को कौशल, तकनीक और रोजगार से जोड़कर भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने वाला

कदम है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹90 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान कर एक सशक्त, स्वस्थ और सक्षम विकसित भारत की आधारशिला रखी गई है। महिला सशक्तिकरण एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को मजबूत करती हैं।

वहीं मध्यम वर्ग और व्यापारियों को कर राहत देकर अधिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे विकसित भारत की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष दिलीप देवतवाल ने कहा, "बजट 2026 केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने का रोडमैप है। गरीब, युवा, महिला और



मध्यम वर्ग को सशक्त किए बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है।" उन्होंने कहा कि जहां विपक्ष केवल भ्रम और नकारात्मकता फैलाने में लगा है, वहीं यह बजट सरकार की विकास, सुशासन और विकसित भारत की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देवतवाल ने कार्यक्रमताओं से आह्वान किया कि वे बजट की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं। निगम प्रयाशी मनीषा बैरवा जी ने कहा कि बजट में शहरी विकास, स्वच्छता, महिला सुरक्षा और रोजगार सृजन से जुड़े प्रावधान नगर निगम स्तर पर भी विकसित भारत की सोच को मजबूती देंगे।

कार्यक्रम में मंडल के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजन संगठनात्मक एकता, राजनीतिक स्पष्टता और विकसित भारत के संकल्प के साथ संपन्न हुआ।

भारतीय कृषक समाज हरियाणा के चेयरमैन एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) के सदस्य अजीत तेवतिया ने विकसित भारत के बजट को सराहनीय एवं आम लोगों के हितों में बताया है।

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय कृषक समाज हरियाणा के चेयरमैन एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) के सदस्य अजीत तेवतिया ने विकसित भारत के बजट को सराहनीय एवं आम लोगों के हितों में बताया है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उपज को बढ़ावा, नारियल किसानों की कृषि को आधुनिक करना। डेयरी, पोल्ट्री, पशुधन को बढ़ावा देते नरी कालेज अस्पताल की योजना से किसान लाभान्वित होंगे। महिला उद्यमियों के लिए शो-

मार्च का गठन, अखरोट बादाम की खेती को बढ़ावा।
क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र खोल कर बुजुर्गों के इलाज पर खास ध्यान केयर इको सिस्टम, स्टॉर्ट अप रिस्कल, टूरिज्म एवं सात दुर्लभ बीमारियों की दवा को सस्ता करना आम जन मानस को राहत किया है युवा गरीब किसान महिलाओं पर फोकस, नए जल मार्ग विकसित करना, सात नए रेल कॉरिडोर बनाये जाने से यात्रा को सुगम किया गया है। बजट 2025-26 देश के नागरिकों के हित में है। और मैनुफैक्चर और इन्फ्रा से देश के विकास को गति मिलेगी।



जनपद लखनऊ में भिक्षावृत्ति से शहर को मुक्त करने हेतु

परिवहन विशेष न्यूज

भिक्षावृत्ति मुक्त लखनऊ अभियान विगत दो वर्षों से निरंतर अभियान संचालित है। जिसमें जिला प्रशासन की ओर से महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर निगम एवं डूडा के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए शहर के मुख्य 19 चौराहा पर निगरानी करने हेतु 7 टास्क फोर्स का गठन करते हुए उनको निर्धारित चौराहा पर निगरानी करने हेतु ड्यूटी लगाई गई है। जिसके तहत वह प्रतिदिन शहर में

भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से आने वाले व्यक्ति महिला, पुरुष एवं बच्चों को भिक्षावृत्ति करने से रोकते हुए समझाकर उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने एवं स्वावलंबन की तरफ ले जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 31.1.2026 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी व एओसीएम-7 के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग

की टीम, थाना गुडबा के पुलिसकर्मी एवं नगर निगम के कार्मिकों के सहयोग से टेढ़ी पुलिया पुल के नीचे अस्थायी रूप से बसावट कर रहे व्यक्तियों को समझाकर वहां से हटाया गया और पुल के नीचे के स्थान को खाली कराया गया जिससे वह आसपास के क्षेत्र में जाकर भिक्षावृत्ति का कार्य न कर सकें तथा टीम का लगातार प्रयास है कि हम भविष्य में लखनऊ जनपद को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने में सफल रहे।

शिक्षा संवाद को नई दिशा दे रहा "टीचर्स ऑफ बिहार" संगठन नहीं, विचार बना शिक्षक सशक्तिकरण का मंच

परिवहन विशेष न्यूज

पटना। राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बोते कुछ वर्षों के दौरान शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी और वैचारिक चेतना में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। इसी बदलाव की पृष्ठभूमि में टीचर्स ऑफ बिहार एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है, जिसने शिक्षकों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर शिक्षा नीति, नवाचार और शिक्षक अधिकारों पर संवाद के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराया है। टीचर्स ऑफ बिहार की पहचान एक ऐसे शिक्षक समूह के रूप में बन रही है, जो बिना किसी औपचारिक संस्थागत दबाव के सहयोग, अनुभव-साझाकरण और रचनात्मक पहल को प्राथमिकता देता है। मंच से जुड़े शिक्षक डिजिटल माध्यमों के जरिये न केवल अपने नवाचार साझा कर रहे हैं, बल्कि सरकारी विद्यालयों की जमीनी चुनौतियों पर भी गंभीर और सार्थक विमर्श कर रहे हैं।

डिजिटल संवाद से बड़ी भागीदारी.... मंच की गतिविधियों में ऑनलाइन बैठकें, शैक्षणिक चर्चाएँ और नवाचार आधारित संवाद प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक भी मुख्यधारा के शैक्षणिक विमर्श से जुड़ पा रहे हैं।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सहभागिता शिक्षा व्यवस्था को अधिक अधिकार और कार्य की गुणवत्ता को महत्व देता है।

मंच से जुड़े शिक्षकों का मानना है कि शिक्षक का वास्तविक सम्मान उसके कक्षा-कक्ष में किए गए नवाचार और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर से तय होता है।

नीतिगत विषयों पर सक्रिय भूमिका....
शिक्षा से जुड़े नीतिगत निर्णयों, शिक्षक हितों और विद्यालयी सुधार से संबंधित विषयों पर टीचर्स ऑफ बिहार समय-समय पर अपने विचार सार्वजनिक करता रहा है। इससे यह मंच शिक्षक और नीति-निर्माण के बीच संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी उभर रहा है।

भविष्य की संभावनाएँ....
शैक्षणिक जानकारों के अनुसार, यदि ऐसे शिक्षक-आधारित मंचों को रचनात्मक समर्थन मिलता रहा, तो यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन का मजबूत आधार बन सकते हैं।

टीचर्स ऑफ बिहार आज एक संगठन से आगे बढ़कर शिक्षा परिवर्तन के साझा विचार के रूप में स्थापित हो रहा है, जहाँ शिक्षक केवल श्रोता नहीं, बल्कि परिवर्तन के सक्रिय भागीदार हैं।

पदाधिकारियों के विचार....
टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर शिव कुमार



भभुआ कैमूर : सीनियर अधिवक्ता चंदौली मिश्रा एवम सीनियर अधिवक्ता वाहिद खा के आवास पर जाकर मिले जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर के अधिवक्ता मंटू पाण्डेय ने लिया हालचाल

भभुआ कैमूर

सीनियर अधिवक्ता चंदौली मिश्रा एवम सीनियर अधिवक्ता वाहिद खा के आवास पर जाकर मिले जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर के अधिवक्ता मंटू पाण्डेय ने लिया हालचाल आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर के अधिवक्ता मंटू पाण्डेय जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर वरीय अधिवक्ता चंद्रमौली मौली मिश्रा 96 वर्षीय से फोन पर हाल चाल लिया। और आज सुबह 9:00 बजे जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर के वरीय अधिवक्ता वाहिद खान 90 वर्षीय से उनके भभुआ आवास पर जाकर उनका हाल-चाल लिया और आशीर्वाद दिया। वारी अधिवक्ता चंद मौली मिश्रा जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर में सन 1963 में सदस्य बने थे भभुआ विधानसभा के

विधायक भी बने थे। सीनियर अधिवक्ता श्री चंद्र मौली मिश्रा अस्वस्थ रहने के कारण न्यायालय जाने में असमर्थ हैं। वर्तमान में सीनियर अधिवक्ता वाहिद खान भी अस्वस्थ रहने के कारण वह भी अपने आवास पर रह रहे हैं वाहिद खान अधिवक्ता 1964 ईस्वी में जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर के सदस्य बने थे और वह 15 बरस तक लगभग लोक अभियोजक के पद पर सविलक कोर्ट भभुआ कैमूर में रहे। अब वह घर पर रह रहे हैं। इन दोनों लोगों के आवास पर जाकर इन लोगों का आशीर्वाद लेने लेकर बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त होता है। इन लोगों से पुरानी पड़ती बनीं हुए जमाने की बातें याद आती है यह दोनों लोग जिला अधिवक्ता संघ भभुआ कैमूर के सबसे सीनियर अधिवक्ता हैं।

रिपोटर संतोष कुमार चतुर्वेदी



NCSL-NIEPA नई दिल्ली के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले मुजफ्फरपुर जिले के प्रधान शिक्षक केशव कुमार को मिला "शिक्षा दीप- नेतृत्व एवं नवाचार सम्मान"।

परिवहन विशेष न्यूज

मुजफ्फरपुर जिले के शत-प्रतिशत प्रारंभिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित माइक्रो इंटरनेट प्रोजेक्ट को दीक्षा पेप पर क्रियान्वित करार पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त कराने में उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन करने वाले मुजफ्फरपुर जिले के जिला तकनीकी टीम के सदस्य-सह-प्रधान शिक्षक केशव कुमार को मिला रजिला स्तरीय उत्कृष्ट तकनीकी सेवा सम्मान 2025-26

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र के द्वारा 17 से 19 जनवरी तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में सफल विद्यालय नेतृत्व उत्सव के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल खर्बड स्थित प्रार्थमिक विद्यालय मोहनपुर उर्दू के प्रधान शिक्षक केशव कुमार को बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव, धीरज साहू, (भा.प्र.से.) ने



सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया था। यह मुजफ्फरपुर जिला सहित पूरे बिहार किए गौरव की बात है। इस उपलब्धि के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर सुजीत कुमार दास ने प्रधान शिक्षक केशव कुमार को रशिक्षा दीप- नेतृत्व एवं नवाचार सम्मान बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर, सुजीत कुमार दास एवं जिला शिक्षा समन्वयक बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर, मनोज कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न रजिला स्तरीय सम्मान 2025-26 के रूप में प्रदान किया गया।

सह-जिले के मुरौल खर्बड स्थित प्रार्थमिक विद्यालय मोहनपुर उर्दू के प्रधान शिक्षक केशव कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, कुमार अरविंद सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर, सुजीत कुमार दास एवं जिला शिक्षा समन्वयक बिहार शिक्षा परियोजना, मुजफ्फरपुर, मनोज कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न रजिला स्तरीय सम्मान 2025-26 के रूप में प्रदान किया गया।



कोरमुला स्थित श्री आई माताजी मंदिर में आयोजित श्री खेतलाजी भैरुजी के जागरण में भजन प्रस्तुत करते मोहनलाल भायल एंड पार्टी। अवसर पर उपस्थित संरक्षक प्रभुराम परिहारिया, अध्यक्ष कालुराम काग, उपाध्यक्ष राजाराम पवार, सह सचिव राजाराम गेहलोत, सभरत कार्यकारी सदस्यगण व अन्य।

युवा बजट 2026-27 के आर्थिक मायने विशिष्ट, विकसित भारत 2047 के सपने होंगे पूरे



कमलेश पांडेय

जहां तक कुल बजट आकार की बात है तो यह 53.5 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया। भले ही राजकोषीय घाटा जीडीपी (GDP) का 4.3% रखा गया, जो पिछले साल के 4.4% की तुलना में कुछ कम है। वहीं, जहां तक कर सुधार की बात है तो आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं आया; जबकि नया आयकर अधिनियम 2026 अप्रैल से लागू होगा। वहीं, एफ एंड ओ (F&O) पर एसटीटी (STT) बढ़ाकर 0.05-0.15% किया गया, विदेशी पर्यटन/शिक्षा हेतु टीसीएस (TCS) 2% किया गया।



बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा। वहीं, राजकोषीय घाटा जीडीपी (GDP) का 4.3% रखा गया, जो पिछले साल के 4.4% की तुलना में कुछ कम है। वहीं, जहां तक कर सुधार की बात है तो आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं आया; जबकि नया आयकर अधिनियम 2026 अप्रैल से लागू होगा। वहीं, एफ एंड ओ (F&O) पर एसटीटी (STT) बढ़ाकर 0.05-0.15% किया गया, विदेशी पर्यटन/शिक्षा हेतु टीसीएस (TCS) 2% किया गया।

जहां तक बजट के क्षेत्रीय प्रावधान किये जाने की बात है तो राजगार-एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ वृद्धि कोष प्रस्तावित है, जबकि क्रेडिट गारंटी दोगुनी की गई है। वहीं, बुनियादी ढांचा हेतु 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का विकास, शहरी विकास के लिए 5,000 करोड़ प्रति वर्ष का प्रस्ताव और स्वास्थ्य-कृषि क्षेत्र में 17 कैसर दवाएं सस्ती किये जाने की घोषणा, बायोफार्मा और मखाना बोर्ड मजबूत किये जाने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं, अन्य महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्यात प्रोत्साहन पर फोकस प्रदान करते हुए सुधारों का 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' जारी रखा गया। लिहाजा, यह विकसित भारत 2047 का रोडमैप है।

इन बजट प्रस्तावों के आर्थिक मायने दूरगामी महत्व वाले हैं, क्योंकि बजट में पूंजीगत व्यय (केपेक्स) को 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है, जो

बजट नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब है और अपार अवसर प्रदान करता है। युवाओं के लिए नया आयाम तथा हर घर लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित करने वाला बताया। विकास फोकस करते हुए उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और समावेशी विकास का माध्यम माना, जो देश को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। विपक्ष की आलोचना के बीच सरकार की सकारात्मक छवि मजबूत करने वाला कदम है।

हालांकि, भारत के 2026-27 बजट पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। विभिन्न दलों ने इसे निराशाजनक, फीका नौकरियों, किसान योजनाएं (मखाना बोर्ड) और स्वास्थ्य (10,000 मेंडिकल सीटें) पर फोकस कर एनडीए (NDA) सहयोगियों व ग्रामीण मतदाताओं को मजबूत संदेश दिया है। जबकि विपक्ष ने इसे 'राजनैतिक बजट' करार दिया है, खासकर राज्य-विशेष घोषणाओं पर, लेकिन विकास लक्ष्य (विकसित भारत 2047) बीजेपी की छवि को मजबूत करेगी। कुल मिलाकर, यह गठबंधन स्थिरता और 2029 के आम चुनाव सहित 2026, 27 और 28 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लिहाजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे सुधारों को मजबूत करने और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रोडमैप करार दिया। मोदी ने कहा कि यह

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौजूदा बजट में भी बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इसे रूढ़िवादी बजट कहा। जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्नसिन्हा ने कहा कि यह बजट उनकी समझ में नहीं आया, इसलिए कोई नंबर नहीं देंगे। कुल मिलाकर विपक्ष ने राज्य-विशेष घोषणाओं की कमी, मध्यम वर्ग व किसानों की अनदेखी तथा राजनैतिक बजट करार दिया।

हालांकि, भारत के 2026-27 बजट पर विपक्ष की आलोचना के जवाब में भाजपा सरकार ने इसे ऐतिहासिक, समावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष नकारात्मक राजनैतिक कर रहा है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को सराहते हुए विपक्ष पर तंज कसा कि वे अर्थव्यवस्था की मजबूती को नहीं देख पा रहे। वहीं, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विकसित भारत के संकल्प में मील का पत्थर करार देते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग के लिए कल्याणकारी है। जबकि यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे विकसित भारत का रोडमैप करार दिया, और कहा कि इसके विभिन्न प्रस्तावों से सामाजिक-आर्थिक विकास का स्वर्णिम अध्याय शुरू होना है। कुलमिलाकर सरकार ने जोर दिया कि कैपेक्स, रोजगार और किसान योजनाएं विपक्ष की 'फीका' टिप्पणी को गलत साबित करेंगी। इस प्रकार यह बजट एनडीए की एकजुटता को भी दिखाता है।



संपादकीय

चिंतन-मगन



कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी; यूनियन बजट 2026 में मरीजों को बड़ी राहत - डॉ यादव



कैंसर दवाएं सस्ती होंगी देश में हर साल 14 लाख कैंसर मामले

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला 1 फरवरी - जीवन-घातक और पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूनियन बजट 2026 में आलख कर्मांशु के कौमलों में भारी कमी की घोषणा की गई है, जिसमें कैंसर और डायबिटीज की दवाएं भी शामिल हैं। संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाना है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने कहा कि इस बजट से कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाएं सस्ती होंगी, साथ ही कैंसर और डायबिटीज सहित सात गंभीर बीमारियों से संबंधित दवाओं की कौमलों में भी कमी आएगी। इस कदम से मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों पर जो लंबे समय तक इलाज पर निर्भर हैं।

सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री पर कस्टम ड्यूटी तथा टैक्स में

तर्कसंगत बदलाव का प्रस्ताव किया है, जिसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगा और सभी के लिए किफायती इलाज के विजन को समर्थन देगा।

दवाओं के अलावा, बजट में उपभोक्ताओं की भी राहत मिली है। मोबाइल फोन, माइक्रोवेव ओवन और कपड़े जैसे कई रोजमर्रा के और घरेलू सामान सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि इनके कर्मांशुओं और कच्चे माल पर ड्यूटी कम की गई है।

हालांकि, बजट में कुछ वस्तुओं की कौमलों में बढ़ोतरी भी संकेतित है। शराब और खनिज-आधारित उत्पादों पर बढ़ी हुई ड्यूटी और संशोधित कर नियमों के कारण ये महंगे हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, यूनियन बजट 2026 ने सार्वजनिक कल्याण और राजस्व संतुलन के बीच संतुलन बनाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत जरूरी राहत देते हुए गैर-आवश्यक और खनिज-आधारित कर उन्मूलन और करों में समायोजन किया गया है।

संतुलन की पतली रस्सी पर बजट 2026

- डॉ० प्रियंका सौरभ

आज 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकार आर्थिक अनुशासन और जनता की आकांक्षाओं के बीच संतुलन पर चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण की शुरुआत ही स्थिरता, निरंतरता और दीर्घकालिक विकास की सोच से की। कोई अप्रत्याशित लोकलुभावन घोषणाओं का धमका नहीं हुआ, बल्कि बजट ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत रखा गया, जो पूर्व निर्धारित 4.5 प्रतिशत लक्ष्य से भी नीचे है। यह कदम वित्तीय अनुशासन की मजबूत मिसाल पेश करता है। पूंजीगत व्यय को पिछले वर्ष के 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया देने के लिए कर छूट, एकल खिड़की प्रणाली और तेज मंजूरी प्रक्रिया जैसे उपाय किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है— निवेशक आइए, हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये विशाल निवेश योजना और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करेगा, या केवल महानगरों की चकाचौंध तक सीमित रहेगा? मध्यम वर्ग, जो देश की जीडीपी में लगभग 40

प्रतिशत योगदान देता है, को इस बजट में ठोस कर राहत मिली है। पुरानी कर व्यवस्था में मानक कटौती को 50,000 रुपये से दोगुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह और अधिक उदार है। नई नई कर व्यवस्था में स्लेबों को सरल बनाया गया—5 लाख रुपये तक की आय पर शुल्क 10% रखा, जो 10 लाख रुपये तक की आय (10 लाख रुपये तक) के लिए 20% रखा गया। दो स्व-व्यवहृत आवासीय संपत्तियों पर कर राहत का प्रावधान, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया। कर संहिता को 819 धाराओं से घटाकर 536 धाराओं में सरलीकृत करने का वादा सराहनीय है। ये कदम कर्मांशुओं को राजस्व का मात्र स्रोत न मानकर भारोई संदर्भित करने की दिशा में हैं। हालांकि, जर्मनी स्तर पर अनुपालन प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा, करना ये राहतें कागजी औपचारिकताओं तक सीमित रह सकती हैं। कृषि क्षेत्र, जो अभी भी 18 प्रतिशत जीडीपी और 65 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का आधार है, पर बजट ने विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना को 100 जिलों में विस्तारित किया गया, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, सिंचाई और भंडारण

क्षमता बढ़ाने पर जोर। पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई। मत्स्य पालन विकास के लिए अंडमान-लक्षद्वीप में आर्थिक क्षेत्र घोषित, फल-सब्जी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का प्रावधान। मनरेगा बजट में वृद्धि, ग्रामीण क्रेडिट र्कोरिंग प्रणाली से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को त्रुणा सुगम। चमड़ा-फुटवियर और खिलौना उद्योगों से 22 लाख नए रोजगार का अनुमान है। ये प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देंगे, लेकिन वास्तविक परीक्षा यही होगी कि क्या ये योजनाएं कागजों से निकलकर खिलौनों को लाभ पहुंचाना चाहिए, न कि बड़े जमींदारों तक सीमित रहना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को प्रार्थमिकता देते हुए लक्ष्मी वंदना योजना का विस्तार, स्वरोजगार ऋण पर गारंटी हटाई गई (20 लाख तक)। शहरी महिलाओं के लिए घर-आधारित कार्य को कर छूट का लाभ। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान हरियाणा जैसे राज्यों में, जहाँ महिला आरक्षण 50 प्रतिशत है, वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा।

देश की 60 प्रतिशत युवा आबादी (35 वर्ष से कम) को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट, जिसमें 50 नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2 लाख करोड़ रुपये, इंटरनेट योजना से 5 करोड़ युवाओं को प्रतिमाह 1 लाख रुपये स्ट्राइपेंड। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता, रोजगार-क्रेडिट विकास मांडल। बीरोजगारी दर को 8 प्रतिशत से नीचे लाने का दृढ़ संकल्प दिखाता है। स्टार्टअप इंडिया फंड को 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन सवाल यही है—क्या ये प्रयास नौकरियों का अवरस बनने, या युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भटकती रहेगी? तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में कुनिम बुद्धिमत्ता (एआई) केंद्र स्थापना, 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से 2 लाख करोड़ राजस्व लक्ष्य। डिजिटल इंडिया को 1 लाख करोड़ रुपये। स्वच्छ ऊर्जा पर 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान—सौर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर 100 प्रतिशत बीमा, जनविश्वस नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा।

देश की 60 प्रतिशत युवा आबादी (35 वर्ष से कम) को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट, जिसमें 50 नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2 लाख करोड़ रुपये, इंटरनेट योजना से 5 करोड़ युवाओं को प्रतिमाह 1 लाख रुपये स्ट्राइपेंड। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता, रोजगार-क्रेडिट विकास मांडल। बीरोजगारी दर को 8 प्रतिशत से नीचे लाने का दृढ़ संकल्प दिखाता है। स्टार्टअप इंडिया फंड को 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन सवाल यही है—क्या ये प्रयास नौकरियों का अवरस बनने, या युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भटकती रहेगी? तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में कुनिम बुद्धिमत्ता (एआई) केंद्र स्थापना, 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से 2 लाख करोड़ राजस्व लक्ष्य। डिजिटल इंडिया को 1 लाख करोड़ रुपये। स्वच्छ ऊर्जा पर 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान—सौर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर 100 प्रतिशत बीमा, जनविश्वस नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा।



संतुलन की पतली रस्सी पर बजट 2026

डिजिटल विभाजन को पाटना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र भी तकनीक से वंचित न रहे। अंत में, चुनौतियां भी कम नहीं। मुद्रास्फूर्ति को 5.5 प्रतिशत पर नियंत्रित रखना, खाद्य महंगाई पर अंकुश। रक्षा बजट 6.5 लाख करोड़ रुपये से सीमा सुरक्षा मजबूत। परिवारवर्ग संरक्षण पर 1 लाख करोड़ रुपये, निर्यात प्रोत्साहन और नवाचार को बढ़ावा। बजट ने दिशा स्पष्ट कर दी है—अब क्रियान्वयन की रफ्तार और ईमानदारी ही परिणाम तय करेगी। बजट 2026 गरीब, किसान, युवा, महिलाओं पर केंद्रित 10 प्रमुख क्षेत्रों का यथार्थवादी रोडमैप है। यह न केवल उम्मीदें जगाता है, बल्कि सवाल भी खड़े करता है। असली कसौटी अमल में होगी—दिशा साफ है, अब गति दिखाने की बारी!

बजट 2026-27 @ विजन 2047- लोकलुभावन के आगे आत्मनिर्भर विकसित भारत की लाजवाब

एवोकेट किशन सनमुखदास भावानी गौदिया महाराष्ट्र गौदिया - वैश्विक लोकप्रिय भारत का आग्र बजट 2026 किसी युवादि वर्ष को ताकालिक लोकप्रियता की लहर में नगा गया दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की घोषणा है जो अब अपने विकास की दिशा स्वयं तय करना चाहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट न तो मानवकानन नरों से भरा है और न ही ताकालिक राज्यों की चकाचौंध में उतारा हुआ। हालांकि बजट पेश होते ही शेरपार्लमेंट सोसाइटी के डेब्ट स्ट्रुक्चर से निरे बजट भाषण शुरू होने से पहले वाला न शिवद का दौर बजट 2 पीव के बाद भी जारी रहा न शिवद न शिवद और स रिज न शिवद, शेरप बाजार से लेकर सोने- चांदी तक में आज के डेब्ट न शिवद सखी रहे, सोने-चांदी में न शिवद का हाल यह रहा कि पिछले एक से दो रफ्त में ज त्रिणा बढ़ा, प्रसे 3 याद प छिते द वि में न रि गयर्ग से इतक सकेरत है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला नहीं गौदिया महाराष्ट्र, यह मानता है कि यह बजट भारत को अपने दो दरकों में एक आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से स्वयं और वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की ठोस रूपरेखा पेश करता है। 17 वर्षों से चली आ रही बजट प्रस्तुती की परंपरा में सुख लैंगिक अर्थपूर्ण बदलाव करते हुए इस बजट के वैश्विक और नीतिगत केंद्र को नए सिरे से परिभाषित किया गया है, जो अपने आप में एक संकेत है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला नहीं रखा गया, बल्कि दोनों को एक ही निरेतर कथान में प्रवेश गया है। यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं, बल्कि वैश्विक है। इसका अर्थ है कि सरकार अब कर नीति, पूंजी निवेश, तकनीकी निवेश और सामाजिक ढांचे को प्राधान्य देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे सुधारों को मजबूत करने और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रोडमैप करार दिया। मोदी ने कहा कि यह

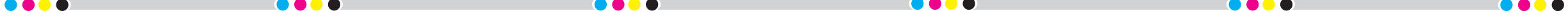
बजट नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब है और अपार अवसर प्रदान करता है। युवाओं के लिए नया आयाम तथा हर घर लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित करने वाला बताया। विकास फोकस करते हुए उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और समावेशी विकास का माध्यम माना, जो देश को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। विपक्ष की आलोचना के बीच सरकार की सकारात्मक छवि मजबूत करने वाला कदम है। हालांकि, भारत के 2026-27 बजट पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। विभिन्न दलों ने इसे निराशाजनक, फीका नौकरियों, किसान योजनाएं (मखाना बोर्ड) और स्वास्थ्य (10,000 मेंडिकल सीटें) पर फोकस कर एनडीए (NDA) सहयोगियों व ग्रामीण मतदाताओं को मजबूत संदेश दिया है। जबकि विपक्ष ने इसे 'राजनैतिक बजट' करार दिया है, खासकर राज्य-विशेष घोषणाओं पर, लेकिन विकास लक्ष्य (विकसित भारत 2047) बीजेपी की छवि को मजबूत करेगी। कुल मिलाकर, यह गठबंधन स्थिरता और 2029 के आम चुनाव सहित 2026, 27 और 28 की विधानसभा चुनाव की तैयारी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लिहाजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे सुधारों को मजबूत करने और विकसित भारत के लिए स्पष्ट रोडमैप करार दिया। मोदी ने कहा कि यह

देश की 60 प्रतिशत युवा आबादी (35 वर्ष से कम) को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट, जिसमें 50 नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2 लाख करोड़ रुपये, इंटरनेट योजना से 5 करोड़ युवाओं को प्रतिमाह 1 लाख रुपये स्ट्राइपेंड। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता, रोजगार-क्रेडिट विकास मांडल। बीरोजगारी दर को 8 प्रतिशत से नीचे लाने का दृढ़ संकल्प दिखाता है। स्टार्टअप इंडिया फंड को 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन सवाल यही है—क्या ये प्रयास नौकरियों का अवरस बनने, या युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भटकती रहेगी? तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में कुनिम बुद्धिमत्ता (एआई) केंद्र स्थापना, 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से 2 लाख करोड़ राजस्व लक्ष्य। डिजिटल इंडिया को 1 लाख करोड़ रुपये। स्वच्छ ऊर्जा पर 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान—सौर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर 100 प्रतिशत बीमा, जनविश्वस नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा।

देश की 60 प्रतिशत युवा आबादी (35 वर्ष से कम) को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट, जिसमें 50 नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2 लाख करोड़ रुपये, इंटरनेट योजना से 5 करोड़ युवाओं को प्रतिमाह 1 लाख रुपये स्ट्राइपेंड। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता, रोजगार-क्रेडिट विकास मांडल। बीरोजगारी दर को 8 प्रतिशत से नीचे लाने का दृढ़ संकल्प दिखाता है। स्टार्टअप इंडिया फंड को 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन सवाल यही है—क्या ये प्रयास नौकरियों का अवरस बनने, या युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भटकती रहेगी? तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में कुनिम बुद्धिमत्ता (एआई) केंद्र स्थापना, 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से 2 लाख करोड़ राजस्व लक्ष्य। डिजिटल इंडिया को 1 लाख करोड़ रुपये। स्वच्छ ऊर्जा पर 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान—सौर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर 100 प्रतिशत बीमा, जनविश्वस नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा।

देश की 60 प्रतिशत युवा आबादी (35 वर्ष से कम) को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट, जिसमें 50 नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2 लाख करोड़ रुपये, इंटरनेट योजना से 5 करोड़ युवाओं को प्रतिमाह 1 लाख रुपये स्ट्राइपेंड। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता, रोजगार-क्रेडिट विकास मांडल। बीरोजगारी दर को 8 प्रतिशत से नीचे लाने का दृढ़ संकल्प दिखाता है। स्टार्टअप इंडिया फंड को 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन सवाल यही है—क्या ये प्रयास नौकरियों का अवरस बनने, या युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भटकती रहेगी? तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में कुनिम बुद्धिमत्ता (एआई) केंद्र स्थापना, 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से 2 लाख करोड़ राजस्व लक्ष्य। डिजिटल इंडिया को 1 लाख करोड़ रुपये। स्वच्छ ऊर्जा पर 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान—सौर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर 100 प्रतिशत बीमा, जनविश्वस नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा।

देश की 60 प्रतिशत युवा आबादी (35 वर्ष से कम) को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट, जिसमें 50 नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2 लाख करोड़ रुपये, इंटरनेट योजना से 5 करोड़ युवाओं को प्रतिमाह 1 लाख रुपये स्ट्राइपेंड। सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता, रोजगार-क्रेडिट विकास मांडल। बीरोजगारी दर को 8 प्रतिशत से नीचे लाने का दृढ़ संकल्प दिखाता है। स्टार्टअप इंडिया फंड को 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन सवाल यही है—क्या ये प्रयास नौकरियों का अवरस बनने, या युवा पीढ़ी नौकरी के पीछे भटकती रहेगी? तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में कुनिम बुद्धिमत्ता (एआई) केंद्र स्थापना, 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से 2 लाख करोड़ राजस्व लक्ष्य। डिजिटल इंडिया को 1 लाख करोड़ रुपये। स्वच्छ ऊर्जा पर 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान—सौर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर 100 प्रतिशत बीमा, जनविश्वस नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा।



परिवहन विशेष के सभी पाठकों के लिए खुशखबरी

संजय कुमार बाटला- मुख्य संपादक



3 फरवरी 2026 से आपके लिए दैनिक समाचार पत्र परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक और English Daily में उपलब्ध हो जाएगा। अब आप परिवहन विशेष को दोनों भाषाओं में आनलाइन और हार्ड कॉपी में प्राप्त कर सकते हैं और अपने लेख, समाचार, कविता, एवम्-अपनी समस्याओं को हमें दोनों भाषाओं में भेज सकते हैं और जनकल्याण जनसूचना जानकारी दोनों भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं।

जल्द ही आप परिवहन विशेष समाचार पत्र को गुरुमुखी और बंगाली भाषा में भी प्राप्त कर पाएंगे।

वर्ष 2026 में ही परिवहन विशेष दैनिक समाचार पत्र 5 भाषाओं में आनलाइन और हार्ड कॉपी में आप सभी पाठकों के लिए संपूर्ण भारत में उपलब्ध हो जाएगा।

इसी के साथ 2027 अंत तक आपको परिवहन विशेष का न्यूज चैनल 24 घंटे के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

आप हम से सच जानने के लिए जुड़े रहे और हमें अपने विचार और समाचार पत्र को आपके प्रति और बेहतर बना कर पहुंचाने के लिए अपने विचार भेजते रहे।

आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं

03 99MC Data shows India added just 21 doctors in a

Nitin Gadkari Sets 5-Year Target To Make India's Auto Industry World's No. 1

Third-largest automobile market, with an industry size of approximately ₹2 lakh crore. The United States remains the largest market at roughly ₹75 lakh crore, followed by China at around ₹60 lakh crore. The minister stressed that India's competitive manufacturing costs and good vehicle quality position it favorably for global leadership. By developing alternative fuels, biofuels, battery electric vehicles, and hydrogen, India can become a global manufacturing hub with a strong export focus. Recommended For You: Toyota Urban Cruiser XE vs e-Vitaran: Design, Range, Features Compared. Global mobility technologies were central to his remarks. Gadkari emphasized that future growth would be anchored not just in conventional automotive production but also in electric vehicles, hydrogen, ethanol and other low-carbon fuel technologies. He acknowledged that the transition to greener vehicles would be gradual, noting that established internal combustion demand would continue.

Medical education body makes nationwide faculty attendance tech go high tech

National Medical Commission

Public notice issued by the NMC secretary Dr. Bhaskar Langer, it was stated. The FACER-based Aadhaar authentication with UIDAI 20 (Registered Device) Service is currently in use in various government offices through the NMC's National Informatics Centre.

De Langer directed the medical colleges and institutions to share the GPS location of different points in the college with NMC so that attendance can be marked within a 50-meter radius of a given GPS location in the college.

A college will have to share GPS locations of points where it wants the convenience of attendance marking via a mobile App, as per the notice marked on all the state and UT health departments. The NMC had last year introduced the AHAAR portal to enhance transparency and reduce manual interference. The idea was to eliminate the need for physical inspections and instead rely on data accuracy and on-site inspections.

All FACER members have to install the FACER-based Aadhaar Authentication App (mobile phone-based) on their mobile phones. The commission further said that the Deans/Principals of all Medical Colleges/Institutions should take necessary action for the installation of the application on the mobile phones of all their faculty members. The App is available on Android Play Store and Apple App Store. The app

School Students Visit Delhi Assembly Exhibition on PM Modi's Journey

A group of school children visited the exhibition titled "Service is the Resolve, India First at the Inspiration - 75 Years, An Experience and An Exhibition" under the aegis of the Ministry of Education, Government of India, at the Parliament Building, New Delhi.

The exhibition offered young minds a meaningful opportunity to engage with India's recent history and leadership. Deputy Speaker...

अमृतसर वेस्ट विधायक ऑफिस में श्रद्धा से मनाई गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती

गुरु रविदास जी ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली कुुरीतियों को मिटाने और समानता का संदेश देने में समर्पित किया- विधायक जसबीर सिंह

अमृतसर, 1 फरवरी (साहिल बेरी)

अमृतसर हल्का वेस्ट ऑफिस में गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती बड़ी श्रद्धा से विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह संघु की ओर से मनाई गयी। गुरु रविदास जी के सुंदर स्वरूप पर फूलों से श्रृंगार किया गया और श्रद्धा के साथ नाम जपते हुए माथा टेका। इस मौके विधायक संघु की ओर से पहुंचे वेस्ट साथियों में लक्ष्मण प्रसाद भी बाटा गया। इस मौके विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह संघु ने कहा कि आज पूरी दुनिया में गुरु रविदास जी की जयंती



श्रद्धा से मनाई जा रही और जगह-जगह पर लंगर लगाए हैं व सोभा यात्रा निकाली जा रही है। विधायक संघु ने कहा कि

15वीं शताब्दी के महान संत, समाज सुधारक और कवि गुरु रविदास जी ने अपना पूरा जीवन

समाज में फैली कुुरीतियों को मिटाने और समानता का संदेश देने में समर्पित कर दिया। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते थे और मानते थे कि ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी लोग, चाहे अमीर हों या गरीब, समान हैं। उनोंने कहा कि

इस दिन संत रविदास के अनूयायी उनकी कही बातों को याद करते हैं। संत रविदास ने अपने जीवन में अनेक दोहों की रचना की। ये दोहे हमारे जीवन को भी नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें उनके दोहे पढ़ने चाहिए और संघ लेनी चाहिए।

इंचार्ज हरप्रीत सिंह बेदी, पापंद विजय भगत, पापंद अमरजीत सिंह गुरटाला, दिलबाग सिंह वडाली, पंकज शर्मा, सुरजीत सिंह खालसा, बलविंदर सिंह गोरा, रविंदर सिंह, सुरजीत सिंह मल्ली, अजय कुमार, पी ए माधव शर्मा आदि उपस्थित थे।

श्रद्धा से मनाई जा रही और जगह-जगह पर लंगर लगाए हैं व सोभा यात्रा निकाली जा रही है। विधायक संघु ने कहा कि

15वीं शताब्दी के महान संत, समाज सुधारक और कवि गुरु रविदास जी ने अपना पूरा जीवन

समाज में फैली कुुरीतियों को मिटाने और समानता का संदेश देने में समर्पित कर दिया। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते थे और मानते थे कि ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी लोग, चाहे अमीर हों या गरीब, समान हैं। उनोंने कहा कि

इस दिन संत रविदास के अनूयायी उनकी कही बातों को याद करते हैं। संत रविदास ने अपने जीवन में अनेक दोहों की रचना की। ये दोहे हमारे जीवन को भी नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें उनके दोहे पढ़ने चाहिए और संघ लेनी चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला का हुआ निर्देश मानसिक स्वास्थ्य व तंत्रिका विज्ञान का दुसरा अस्पताल पुनः रांची मे

मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी यूनिट देने की घोषणा की, उत्तर भारत को मिलेगा फायदा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, केंद्रीय बजट में झारखंड को हेल्थ सेक्टर में बड़ी सीमा मिली है। राजधानी रांची में राज्य को अपना पहला NIMHANS मिलने वाला है, जिससे उत्तरी भारत में मेटल हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। रांची पहले से ही अपने मेटल हेल्थ संस्थानों के लिए जानी जाती है।

सिआईपी अधिकारियों ने इस घोषणा पर खुशी जताई है और कहा है कि वे NIMHANS की तंत्र पर संस्थान को अपग्रेड करने की मांग कर रहे हैं। इस संस्थान की स्थापना अंग्रेजों ने 17 मई, 1918 को रांची यूरोपियन ल्यूनेटिक असाइलम नाम से की थी।



उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि आने वाले फाइनेंशियल इयर में बजट पास हो जाएगा। यह सबसे बड़े अपग्रेड में से एक होगा और इससे झारखंड और आसपास के राज्यों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि CIP 220 एकड़ में फैला हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम आने वाले फाइनेंशियल इयर में प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे।

संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। इसलिए रांची NIMHANS 2.0 स्थापित करेंगे और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को भी क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में काम करेंगे।

ओल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन आफ आसाम के मंच पर तिनसुकिया पहुंचे हेमंत सोरेन बौद्धिक व आर्थिक रूप से मजबूत लोगों ने झारखंड को 15 साल पीछे ढकेलने का प्रयास किया : हेमंत सोरेन

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज असम के तिनसुकिया जिला में ओल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम द्वारा आयोजित ₹21 वीं आदिवासी महासभा-2026 के संबोधित करते हुए कहा कि यहां आप सभी आदिवासी समुदाय के लोग जो लगभग डेढ़ सौ वर्षों से यहां रह रहे हैं उनसे रू-ब-रू होना का आज मुझे मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के वैसे सभी आदिवासी-मूलवासी समुदाय के जनमानस को असम में रह कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनकी तकलीफों, उनपर हो रहे अत्याचारों और व्यथा को सुनने के लिए हम आज यहां आए हैं। हम लोग झारखंड से आए हैं, कहीं न कहीं आप सभी का जुड़ाव भी झारखंड से बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जब देश के लोग आजादी का सपना भी नहीं देखे थे, उस समय आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। देश की आजादी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, तिलका मांझी सहित झारखंड के अनगिनत वीर सपूतों का अहम योगदान

कई नीतियां-कानून बने। देश के संविधान से हमें रक्षा कवच मिला उसके बावजूद आज हम कहां खड़े हैं। आज हमारा समाज कितना संघर्ष कर रहा है यह बहुत बेहतर तरीके से आप सभी लोग जानते हैं। आज सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से आदिवासी समुदाय कमजोर है और इसी कमजोरी का फायदा बड़े एवं सामंती विचारधारा वाले लोग बहुत चालाकी से उठाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय दिशोम मरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं हैं, जब उन्होंने अलग राज्य की प्रतिकल्पना की तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि आदिवासी लोग अलग राज्य बनाएंगे। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। वर्ष 2000 में अलग झारखंड राज्य झारखंड बना। यह बात सही है कि उस समय क्या नारा लगता था, कैसे लगे झारखंड, लड़के लगे झारखंड। उस समय न मोमाल, न गाड़ी, न मोटर उसके बावजूद झारखंड के लोग जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए चोटियों की तरह एकजुट हो जाते थे। राज्य अलग हुआ लेकिन इसका फायदा आदिवासी समुदाय को नहीं मिला। हम लोगों को तो राज्य लेना

था, हमारे अग्रणी नेताओं ने सोचा कि राज्य अलग होगा तो यहां के आदिवासियों-मूलवासियों का विकास होगा। झारखंड राज्य अलग होने के बाद बौद्धिक रूप से मजबूत लोगों ने 15 वर्ष से ज्यादा समय तक झारखंड को पीछे धकेलने का काम किया, नतीजा यह हुआ कि राशन कार्ड लेकर लोग भात-भात-कढ़ते हुए भूख से मरने को विवश हुए, फिर हमने प्रखंड-प्रखंड, गांव-गांव, टोला-टोला पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम किया फिर लोगों ने हमें राज्य की बागडोर संभालने का मौका दिया। राज्य का

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत की अपील

पिकी कुंहु

कल से नकद राशि में भीख देना बंद कर दी जाए बिखारियों को (भोजन + पानी) जरूर दे, लेकिन एक भी रुपया केश नहीं दे।

पूरे जयपुर में इस तरह का एक अलग आंदोलन शुरू हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार का बिखारी हो वहां के लोगों ने प्रण किया है कि वह नकद राशि में किसी भी बिखारी को भीख नहीं देंगे, मदद करेंगे वह कपड़े, फल और भोजन के रूप में और यह आंदोलन बिब्लुक सहि है।



आप भी प्रण लें चाहे कोई भी (महिला / पुरुष / वृद्ध / दिव्यांग / बच्चा) भीख मांग रहा हो, आप पैसे की बजाय (भोजन + पानी) देंगे, लेकिन आज से पैसे की भीख नहीं देंगे।

श्री हनुमान धाम में 18 फरवरी को होगा भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव



अमृतसर 1 फरवरी + साहिल बेरी

जय श्री राम के उद्घोष के साथ ए-ब्लॉक, श्री गुरु तेग बहादुर नगर, माल मंडी स्थित श्री हनुमान धाम में भगवान श्री हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ किया जा रहा है। यह पावन आयोजन 15 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। आयोजकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कार्यक्रमों की शुरुआत 15 फरवरी 2026 (रविवार) को प्रातः

10:00 बजे हवन के साथ होगी। इसके उपरांत प्रातः 11:00 बजे कलश यात्रा तथा दोपहर 1:00 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 16 फरवरी 2026 (सोमवार) को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक जलवास-अवसास का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक महास्नान एवं महानिवास की विधियां संपन्न होंगी। मुख्य आयोजन 18 फरवरी 2026

(बुधवार) को प्रातः 9:00 बजे से प्राण प्रतिष्ठा पूजा के साथ आरंभ होगा, जबकि दोपहर 12:00 बजे पूर्ण आहुति डाली जाएगी। पूर्ण आहुति के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इस पावन अवसर पर श्री हनुमान सेवा परिवार ट्रस्ट (रज.) द्वारा समस्त भक्तजनों एवं उनके परिवारों को सादर आमंत्रित किया गया है। आयोजकों ने अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं से उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की है।

श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर डॉ गुप्ता ने विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचकर गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया

अमृतसर, 1 फरवरी (साहिल बेरी)

2026 सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत श्री गुरु रविदास जी की 649 वीं जयंती पर केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ अजय गुप्ता ने शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंच कर गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया तथा गुरु चरणों में सरबत के भले की अरदास की। विधायक डॉ गुप्ता ने भूषणपुरा क्षेत्र, हॉल गेट, शक्तिनगर, गोल हट्टी चौक और अन्य क्षेत्रों में श्री गुरु रविदास जी मंदिर में नतमस्तक हुए, जहां आयोजक कमेटे के सदस्यों द्वारा विधायक डॉ अजय गुप्ता को सम्मानित भी किया गया।

विधायक डॉ गुप्ता ने सभी को श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने समय में गैर बराबरी पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर चोट की थी। गुरु जी के दोहे 'ऐसा चाहुँ राज मैं मिले सबों को अन्न छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न' का उच्चारण करते हुए विधायक डॉ गुप्ता ने कहा



कि इस दोहे के माध्यम से गुरु रविदास जी ने सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को मिटाकर सामाजिक एवं आर्थिक क्षमता की वकालत की। विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने संतगुण और कीर्तन के माध्यम से निर्गुण भक्ति करते हुए जगह-जगह घूम कर देश के दलित पीड़ित शोषित समाज को जागृत करने का काम किया। आज भी

उनके जीवन और संघर्षों से प्रेरणा लेकर समाज को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने सभी को गुरु जी दर्शाए मार्ग पर चलते हुए अपने गुरुओं और महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने गुरु रविदास जी के जीवन और संघर्षों से प्रेरणा लेकर समाज में व्याप्त जातिवाद एवं अन्य विषमता को दूर करने की भी अपील की।